● वर्ष : 17 ● अंक : 227 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

दैनिक लोकतंत्र की शान

WWW.LKSTV.IN

दिल्ली से प्रकाशित रविवार 07 जून 2026 लोकतंत्र का स्तंभ

पीएम ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ की चर्चा

एजेंसी। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएम-ईएसी) के सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और गति देने के उपायों पर व्यापक चर्चा की गई। प्रधानमंत्री और परिषद के सदस्यों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न विचारों और नीतिगत उपायों पर विचार-विमर्श किया। इसके साथ ही आम नागरिकों के जीवन को अधिक सुगम बनाने तथा कारोबार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को बढ़ावा देने संबंधी सुधारों पर भी चर्चा हुई। बैठक में परिषद के सदस्यों ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का भी आकलन प्रस्तुत किया। ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार, निवेश और वैश्विक आर्थिक स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर विचार साझा किए गए। सरकार का मानना है कि अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और दीर्घकालिक विकास के लिए सुधारों तथा निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीतने पर प्रज्ञानानंद को दी बधाई

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद को नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने पर बधाई दी है। प्रज्ञानानंद इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, "इस शानदार उपलब्धि के लिए प्रज्ञानानंद को बधाई। यह वास्तव में एक अविश्वसनीय उपलब्धि है, जो उनकी निरंतर उत्कृष्टता को दर्शाती है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। उल्लेखनीय है कि आर. प्रज्ञानानंद का पूरा नाम रमेशबाबू प्रज्ञानानंद है। उनका जन्म 10 अगस्त 2005 को चेन्नई में हुआ था। उन्होंने वर्ष 2018 में महज 12 वर्ष की आयु में ग्रैंडमास्टर बनकर दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर्स में अपनी जगह बनाई थी। प्रज्ञानानंद ने वर्ष 2022 में ऑनलाइन रैपिड टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थीं। अब नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतकर उन्होंने भारतीय शतरंज के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है।

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत पहुंचे जंतर-मंतर

एजेंसी। नई दिल्ली

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन शुरु हो गया है। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके भी वहां मौजूद हैं। हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाए जा रहे हैं। अभिजीत शनिवार सुबह 7:45 बजे अमेरिका से सीधे दिल्ली पहुंचे। वे करीब एक घंटे बाद एयरपोर्ट से बाहर आए। बाहर आने में देरी की वजह सामने नहीं आई। अभिजीत ने बाहर आकर अंबेडकर की किताब को हाथ में उठाया। इस किताब को लेकर वे प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जंतर-मंतर पर सीजेपी का यह पहला प्रदर्शन है। यह विरोध नीट-यूजी पेपर लीक और सीबीएसई, सीयूईटी एसएससी-जीडी जैसी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके से सीजेपी के समर्थकों से कहा है कि आंदोलन को प्रेम और शांति से आगे बढ़ाना है। कॉकरोच इज़ बैक एक्स हैंडल ने लिखा है, दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मंजूदी दे दी है।

अब हम सीधे जंतर मंतर पर इकट्ठा हो सकते हैं और हमें पहले की योजना के मुताबिक पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले अभिजीत ने एक्स पर लिखा- लैंड कर चुका हूं। जल्द ही आप सब से जंतर मंतर पर मिलने का इंतज़ार है। किताब और हमारा तिरंगा साथ लाना मत भूलना। उन्होंने आगे लिखा- पुलिसकर्मियों को फूल दें, यह करुणा और आभार का प्रतीक होगा।

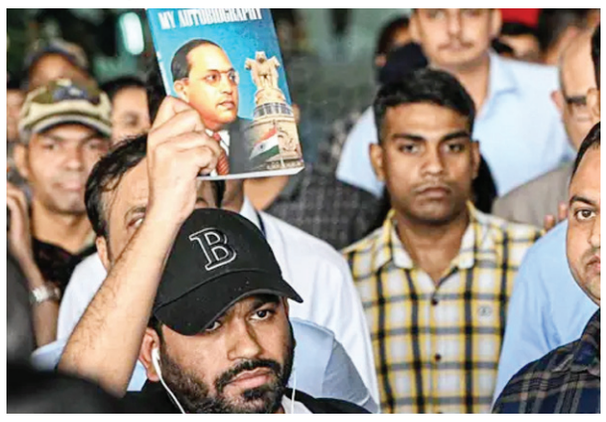

ज्वलंत मुद्दा **संपादकीय**

आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपैया के चक्कर में फंसी अर्थ -व्यवस्था

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आज देश में एक गंभीर बहस चल रही है। एक पक्ष का मानना है, कि 2004 से 2014 के बीच, विशेषकर 2011 तक, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल थी। उस दौर में भारत की तुलना चीन, अमेरिका, रुस एवं अन्य यूरोपीय देशों के साथ वैश्विक मंचों पर होने लगी थी। सूचना प्रौद्योगिकी, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण तथा लघु एवं मध्यम उद्योगों के विस्तार ने देश को नई आर्थिक ऊँचाइयों तक पहुँचाया था।

2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान जब अमेरिका और यूरोप की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ संकट से जूझ रही थीं, तब भारत अपेक्षाकृत मजबूत आर्थिक स्थिति के साथ खड़ा दिखाई दिया। अनेक अर्थशास्त्रियों का मानना था, भारत के विशाल घरेलू बाजार, असंगठित क्षेत्र तथा लघु एवं मध्यम उद्योगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही कारण था, उस समय भारत को वैश्विक आर्थिक क्षेत्र के केंद्र बिन्दू के रूप में देखा जाने लगा था। लेकिन 2011 के बाद भारत का राजनीतिक माहौल तेजी से बदला। भ्रष्टाचार के आरोप, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्टों तथा अन्ना हजारे के नेतृत्व में चले जनलोकपाल आंदोलन ने तत्कालीन सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया।

सरकार की छवि पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसमें विदेशी ताकतों का हाथ भी बताया जाता है। कारपोरेट जगत भी मनमोहन सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया था। इस तरह से सारा विपक्ष कांग्रेस और मनमोहन के खिलाफ खड़ा हो गया था। अंततः 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ। आलोचकों का आरोप है कि उस समय देश की आडिट रिपोर्ट में लगाए गए कई आर्थिक नुकसान के अनुमान न्यायिक प्रक्रिया में प्रमाणित नहीं हो सके, काल्पनिक आरोपों से तब तक राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल चुका था।

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य को लेकर भी गंभीर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि पिछले एक दशक में ऐसी नीतियाँ अपनाई गईं, जिनसे बड़े कॉर्पोरेट समूहों को लाभ मिला, जबकि लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। नोटबंदी, जीएसटी के प्रारंभिक क्रियान्वयन और महामारी के प्रभाव ने छोटे व्यवसायों की कमर तोड़ दी। लाखों सूक्ष्म इकाइयाँ बंद हुईं। रोजगार के अवसर सिमटते चले गए। अर्थ- व्यवस्था में एक अन्य चिंता भारत के बढ़ते आयात और घटती विनिर्माण क्षमता को लेकर है। चीन से बड़े पैमाने पर उपभोक्ता वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक उत्पादों का आयात लगातार बढ़ा है।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.9911371802
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER786@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनने देंगेः ट्रंप

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि तेहरान के साथ जारी टकराव अब खत्म होने के करीब है। उन्होंने दृढ़ता के साथ ऐलान किया कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को 'किसी न किसी तरह' हर हाल में रोका जाएगा। विस्कॉन्सिन के चिप्पेवा फॉल्स में कृषि से जुड़ी एक अहम बैठक को संबोधित करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार संपन्न देश बनने से रोकने का अपना मुख्य उद्देश्य काफी हद तक हासिल कर लिया है। उन्होंने वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका किसी भी सूरत में परमाणु हथियार का खतरा बर्दाश्त नहीं करने वाला था और अब यह काम लगभग पूरा हो चुका है। ट्रंप के मुताबिक, यह गतिरोध या तो किसी कूटनीतिक समझौते के जरिए खत्म होगा या फिर इसके लिए कोई सख्त रास्ता अख्तियार किया जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस संबंध में चल रही किसी संभावित बातचीत या सैन्य कार्रवाई की रूपरेखा को लेकर कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की, लेकिन उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए कि ईरान से जुड़े घटनाक्रम जल्द ही दुनिया के सामने पूरी तरह साफ हो जाएंगे। उन्होंने इस भू-राजनीतिक स्थिति को सीधे तौर पर वैश्विक ऊर्जा बाजार और अमेरिकी किसानों की आर्थिक स्थिति से जोड़ा। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि ईरान संकट के समाधान से आर्थिक दबाव को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी, जिससे तेल, गैस और ऊर्जा की कीमतें काफी घट जाएंगी।

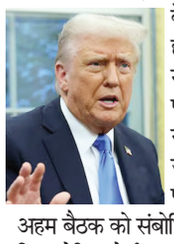

बंगाल में जिनके नाम एसआईआर में कटे अब उनके होंगे राशन कार्ड रद्द

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के खजाने पर बढ़ रहे अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करने और सरकारी योजनाओं में हो रही धांधली को रोकने के लिए अभियान शुरू किया है। सरकार ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की खाद्य साथी योजना के तहत मुफ्त और सस्ते अनाज का लाभ ले रहे अपात्र और फर्जी लाभार्थियों को बाहर करने का फैसला किया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक एसआईआर के नतीजों के आधार पर उन सभी राशन कार्डों को चिह्नित कर डिलीट किया जाएगा जो नियमों के तहत अयोग्य पाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आदेश में साफ कहा गया है कि एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से जिन 63 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनकी पहचान की जाएगी और उनके राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। हालांकि, सरकार ने इसमें एक मानवीय और कानूनी पहलू को भी शामिल किया है। आदेश में कहा गया है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं, लेकिन उन्होंने सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है या ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील की है उनके राशन कार्ड तब तक एक्टिव रहेंगे जब तक कि उनकी याचिकाओं पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता।सीएम अधिकारी द्वारा कुछ दिनों पहले शुरू की गई अन्नपूर्णा योजना के लिए सरकार ने एक नया आवेदन फॉर्म भी पेश किया है।

ममता को एक ओर झटका, टीएमसी के पांच पार्षद कांग्रेस में हुए शामिल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद टीएमसी में टूट पड़ चुकी है। एक ओर ममता बनर्जी के सामने पार्टी को बचाने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इस बीच ममता को एक और बड़ा झटका लगा है, जब कूचबिहार जिले की मेखलीगंज नगर पालिका के अध्यक्ष और पांच पार्षदों ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसके बाद नगर निकाय पर अब कांग्रेस का कब्जा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल के उत्तरी हिस्से में हुआ यह राजनीतिक घटनाक्रम टीएमसी के अंदर जारी उथल-पुथल और सिलसिलेवार दलबदल के बीच सामने आया है, जिसने राज्यभर में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को हिलाकर रख दिया है। 9 वार्ड वाली मेखलीगंज नगरपालिका पर टीएमसी का नियंत्रण था, जिसमें पार्टी के 8 और बीजेपी का एक पार्षद था। अब अध्यक्ष प्रभात पाटनी और पांच अन्य पार्षदों के पाला बदलने से कांग्रेस नगर पालिका में बहुमत में आ गई है और उसने टीएमसी से इस नगरपालिका की सत्ता छीन ली है। हालांकि, एक पार्षद ने संकेत दिया है कि वह टीएमसी में बने रहेंगे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पाटनी ने कहा कि आगे और दलबदल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोलकाता स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी में शामिल हुआ हूं। मेखलीगंज लौटने के बाद दो और पार्षद भी औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होंगे। टीएमसी छोड़ने के कारणों पर उन्होंने कहा कि पार्टी आंतरिक संघर्षों में उलझी हुई है, जिससे जनता के लिए काम करना मुश्किल हो गया है। पाटनी ने कहा कि टीएमसी के अंदर रहकर अब काम करना संभव नहीं है।

सीमा सुरक्षा में बड़ा बदलावः घुसपैठ रोकने के लिए शुरू होगी 'स्मार्ट बॉर्डर' परियोजना

एजेंसी। नई दिल्ली

शाह ने कहा, सीमा सुरक्षा को मजबूत करना केंद्र की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में

देश की सीमाओं को अधिक सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि जल्द ही देश की सीमाओं पर सात से आठ स्थानों पर 'स्मार्ट बॉर्डर' पायलट परियोजना शुरू होगी। इस योजना का उद्देश्य घुसपैठ, तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी ठंग से रोक लगाना है। त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर बीएसएफ जवानों को संबोधित केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि सरकार सीमा पार से होने वाली घुसपैठ के जरिए किसी भी प्रकार के जनसांख्यिकीय बदलाव को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि चाहे त्रिपुरा हो, बंगाल हो या बिहार, सीमा सुरक्षा को मजबूत करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना में आधुनिक तकनीक, स्थानीय प्रशासनिक संसाधनों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। यह योजना मौजूदा बाड़बंदी व्यवस्था का पूरक होगी और सीमाओं को अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षित बनाने में मदद करेगी।

उन्होंने बताया कि परियोजना की रूपरेखा करीब अंतिम चरण में है और शुरुआती चुनौतियों को दूर करने के बाद पूरे सीमा क्षेत्र में लागू होगी। केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश से लगी करीब 650 किलोमीटर लंबी सीमा पर मौजूद 15 वर्ष से अधिक पुरानी 119 किलोमीटर बाड़ को बदलने की मंजूरी दे दी गई है। इससे सीमा प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश को सीमावर्ती क्षेत्रों में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, ड्रोन के माध्यम से नकली मुद्रा और अन्य अवैध गतिविधियां शामिल हैं। शाह ने जोर देकर कहा कि सुरक्षित राष्ट्र का अर्थ केवल बाहरी सैन्य खतरों से रक्षा नहीं है, बल्कि तस्करी, नशे और आर्थिक अपराधों से भी देश को सुरक्षित रखना है। केंद्रीय गृह मंत्री की यह यात्रा राजस्थान और गुजरात की सीमाओं के निरीक्षण के बाद हुई है। माना जा रहा है कि वह जल्द ही पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों का भी दौरा कर सकते हैं।

ओम बिरला 8 जून को करेंगे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक का उद्घाटन

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 8 जून को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभा में द्वितीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र जोन II उत्तर जोन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा और उपस्थित विशिष्टजनों को संबोधित करेंगे। इस दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधि भविष्य की चुनौतियों से निपटने और 'विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में जागरूक समाज और विधि-निर्माताओं की भूमिका' विषय पर विचार-विमर्श करेंगे। सम्मेलन की समाप्ति 9 जून को हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष के समापन भाषण के साथ होगी। समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष कल्याण और अन्य विशिष्टजन उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन में सीपीए भारत क्षेत्र जोन-II के पांच विधानमंडलों के सभापति, अध्यक्ष, उप सभापति और उपाध्यक्ष सहित पीठासीन अधिकारी, विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्य और केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, हरियाणा विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल होंगे।

भारत, चीन व रुस के घनिष्ठ मित्र

भारत-रूस-चीन संबंधों पर पुतिन का आया बयान, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में आरआईसी का बड़ा योगदान

नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत, चीन और रूस के संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण बयान देकर कहा कि तीनों देशों के बीच सहयोग स्वाभाविक रूप से विकसित हो रहा है और यह दुनिया भर में सभी पक्षों के हित में है। उन्होंने साफ किया कि भारत और चीन दोनों रूस के घनिष्ठ मित्र हैं तथा दोनों देशों के बीच मौजूद मुद्दों को आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। एक इंटरव्यू में पुतिन ने भारत-चीन संबंधों पर टिप्पणी कर कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बहुआयामी और संवेदनशील हैं। उनके अनुसार, रूस इन संबंधों में हस्तक्षेप करने के बजाय दोनों पक्षों के साथ मित्रतापूर्ण संवाद बनाए रखता है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सीमा विवाद सहित सभी लंबित मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए प्रयासरत हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस के भारत और चीन दोनों के साथ मजबूत संबंध हैं और इनमें किसी प्रकार का टकराव नहीं है। उनके मुताबिक, रूस-भारत संबंधों से चीन को कोई परेशानी नहीं और न ही रूस-चीन सहयोग भारत के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस तरह का सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए लाभकारी है।

सीयूईटी रिजल्ट में देरी से डीयू दाखिला प्रक्रिया पर संकट, शैक्षणिक कैलेंडर बिगड़ने की आशंका

एजेंसी। नई दिल्ली

देश की प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं को लेकर जारी विवादों और तकनीकी चुनौतियों का असर अब उच्च शिक्षा संस्थानों पर दिखाने लगा है। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया फिर विलंबित होने की आशंका है, क्योंकि विश्वविद्यालय कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी-यूजी) के परिणाम घोषित होने का इंतजार कर रहा है। इस स्थिति ने शिक्षकों और शिक्षा विशेषज्ञों के बीच शैक्षणिक कैलेंडर के लगातार प्रभावित होने को लेकर चिंता बढ़ी है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, स्नातक प्रवेश प्रक्रिया सीयूईटी-यूजी के परिणाम आने के बाद ही शुरू होगी। डीयू की डीन ऑफ एडमिशन हनीत गांधी ने कहा कि विश्वविद्यालय अनावश्यक देरी से बचने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर रहा है, लेकिन प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत परीक्षा परिणामों पर निर्भर करेगा। इसके पहले संकेत दिए थे कि पंजीकरण प्रक्रिया मई के 3 सप्ताह में शुरू हो सकती है, लेकिन परिस्थितियां बदलने के कारण यह संभव नहीं हुआ। दरअसल, इस वर्ष सीयूईटी-यूजी परीक्षा तकनीकी बाधाओं से प्रभावित रही। 30 मई को तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा संचालन में व्यवधान आया, इसकारण राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा। प्रभावित 3,700 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा आयोजित करने का निर्णय हुआ। इसी वजह से परिणाम जारी होने की समय-सीमा भी आगे खिसक गई है। शिक्षकों का मानना है कि यह कोई नई समस्या नहीं है। 2022 में सीयूईटी लागू होने के बाद से डीयू का शैक्षणिक कैलेंडर लगातार प्रभावित होता रहा है। वर्ष 2025 में भले ही कक्षाएं 1 अगस्त से शुरू हो गई थीं, लेकिन सितंबर के अंत तक प्रवेश और मॉप-अप राउंड चलते रहे, इससे अनेक छात्र सत्र शुरू होने के कई सप्ताह बाद कक्षाओं से जुड़े।

स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए सकारात्मक बदलाव, कांग्रेस इसको स्वीकार करने से बच रहीः जेपी नड्डा

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय को राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित करना उचित नहीं है। खरगे की जानकारी अधूरी और खतरनाक है। सिर्फ चुनिंदा आंकड़ों के आधार पर तस्वीर पेश करने के बजाय पूरे परिदृश्य को देखना चाहिए। जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों का हवाला देते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में कहा कि कांग्रेस देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए सकारात्मक बदलावों को स्वीकार करने से बच रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं। एनएफएचएस -3 (2005-06) की तुलना में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रमुख संकेतकों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। नड्डा ने कहा कि गर्भावस्था की पहली तिमाही में पंजीकरण कराने वाली महिलाओं का प्रतिशत 43.9 से बढ़कर 76.2 हो गया है। वहीं संस्थागत प्रसव 38.7 से बढ़कर 90.6 प्रतिशत और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में होने वाले प्रसव 46.6 से बढ़कर 91.3 प्रतिशत तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े केवल संख्या नहीं हैं, बल्कि करोड़ों महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित प्रसव और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलने का प्रमाण हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत की स्वास्थ्य यात्रा की वास्तविक कहानी निराशा नहीं, बल्कि निरंतर प्रगति और सुधार की है। कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा कि सबसे चिंताजनक बात यह है कि वह देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए सकारात्मक बदलावों को स्वीकार करने से बच रही है। दशकों तक भारत कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं, सीमित चिकित्सा पहुंच और कमजोर सेवा वितरण प्रणाली की चुनौतियों से जूझता रहा, जिसके प्रभाव कई पीढ़ियों तक दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े आज एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। देश में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ी है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई हैं, सामाजिक सुरक्षा का दायरा विस्तृत हुआ है और कई प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किए गए हैं।

ऑपरेशन ब्लू स्टार बरसी पर स्वर्ण मंदिर परिसर में लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे

अमृतसर। भारतीय इतिहास के सबसे संवेदनशील सैन्य अभियानों में से एक ऑपरेशन ब्लू स्टार की आज 42वीं बरसी है। इस मौके पर पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर में फिर अलगाववादी स्वर सुनाई दिए। सिखों की सर्वोच्च धार्मिक पीठ श्री अकाल तख्त साहिब पर भीड़ जमा हुई, जहां जरनैल सिंह भिंडरावाले के समर्थन में पोस्टर लहराए गए और खालिस्तान के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। श्री अकाल तख्त साहिब के पास इकट्ठा हुए चरमपंथी और सिख संगठनों के समर्थकों ने हाथों में तख्तियां और जरनैल सिंह भिंडरावाले के बड़े-बड़े पोस्टर ले रखे थे। इस दौरान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों और कई संगठनों द्वारा हर साल 6 जून को विशेष अरदास की जाती है, जिसमें जरनैल सिंह भिंडरावाले और ऑपरेशन के दौरान मारे गए अन्य लोगों को याद किया जाता है। बरसी की संवेदनशीलता को देखते हुए हर साल की तरह पंजाब पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा अमृतसर और विशेषकर स्वर्ण मंदिर के आसपास सुरक्षा के कड़ी कर दी गई हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके और शांति कायम रहे।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEU-TICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

संक्षिप्त समाचार

मंत्री सिरसा ने रघुवीर नगर के लोगों से किया संवाद, समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को रघुवीर नगर का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया। स्थानियों लोगों ने सड़कों की स्थिति, नालियों की सफाई, पानी की लाइनों और सीवेज से जुड़े मामलों पर मंत्री के सामने बात रखी। यह जानकारी मंत्री अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर साझा की।मंत्री सिरसा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को इन समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की देरी न करने का निर्देश दिया है। उन्होंने किए जाने वाले कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सीधे उन्हें सौंपने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि कर्तव्य है। मंत्री सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हम 'दफ्तरों से नहीं, जनता के बीच' सरकार चलाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट का बीसीडी के दोबारा चुनाव कराने से इनकार

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) के दोबारा चुनाव कराने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि भले ही चुनाव में कथित रुप से अनियमितताओं और बैलेट पेपर्स से छेड़छाड़ की शिकायतें मिली हैं लेकिन कोर्ट दोबारा चुनाव कराने का आदेश नहीं देगा। कोर्ट ने मतगणना शुरु करने का आदेश दिया। मतगणना वहीं से शुरु होगी जहां से बंद की गई थी।कोर्ट ने कहा कि केवल कुछ बैलेट पेपर में छेड़छाड़ की शिकायत के आधार पर नये सिरे से चुनाव कराने की जरुरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जिस मत पत्र में जिसमें इरेजर, ओवरराइटिंग, करेक्शन या जोड़ने की शिकायत मिले उसे अलग कर उन्हें संदेहास्पद मत पत्र की श्रेणी वाले पैकेट में रखा जाए। इन संदेहास्पद मत पत्रों को एएसजी के समक्ष लाया जाए, जो ये तय करेंगे कि उनकी गिनती कैसे हो, उन पर एएसजी का ही अंतिम फैसला होगा।कोर्ट ने कहा कि प्रथम वरीयता वाले मत पत्रों की गिनती की कोई जरुरत नहीं है क्योंकि गड़बड़ियों की जो शिकायतें मिली हैं उनमें प्रथम वरीयता वाले मत शामिल नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि मतगणना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मत पत्रों को बंद किए जाने लायक स्टोरेज में रखने, हाई रिजोल्यूशन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे से लगातार निगरानी और उनका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा काउंटिंग स्टाफ का कड़ाई से सत्यापन किया जाए।कई उम्मीदवारों ने मतगणना में गड़बड़ी की शिकायत करते हुए याचिका दायर की थी। इसके पहले 18 मई को उच्चतम न्यायालय ने बीसीडी के चुनाव की मतगणना पर रोक लगा दी थी। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को भेज दिया था, जिसके बाद उच्च न्यायालय इस पर सुनवाई कर रहा था।उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि मामले के प्रभावी निपटारे के लिए मूल रिकॉर्ड और बैलेट पेपर्स की जांच जरुरी होगी, इसलिए इस मामले की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना ही उचित होगा। बीसीडी का चुनाव 21, 22 एवं 23 फरवरी को हुआ था। बीसीडी चुनाव की गिनती 7 अप्रैल से शुरु हुई थी। इस चुनाव में 221 उम्मीदवार मैदान में हैं।

फिरोजपुर सड़क हादसे पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की सहायता

लोकतंत्र की शान :नई दिल्ली। पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुए सड़क हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया। तीनों नेताओं ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि फिरोजपुर, पंजाब में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने शोक-संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने भी हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि फिरोजपुर जिले में हुई इस दुखद सड़क दुर्घटना की खबर से वह अत्यंत व्यथित हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र एवं पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना की।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि फिरोजपुर जिले में हुए हादसे की खबर से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

दिल्ली में वर्षा जल संचयन को मिलेगा बढ़ावा, 50 हजार रुपये तक की सहायता और बिल में छूट देगी सरकार

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने जल संरक्षण और भूजल स्तर में सुधार के उद्देश्य से वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) को व्यापक जनभागीदारी का अभियान बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "कैच द रेन" अभियान की भावना को आगे बढ़ाते हुए राजधानी में जल संरक्षण को नई गति दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य हर बूंद वर्षा जल को संरक्षित कर जल-सुरक्षित दिल्ली का निर्माण करना है।मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार वर्षा जल संचयन प्रणाली को अपनाने वाले नागरिकों और संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसके तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने पर लोगों को 50 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही ऐसे उपभोक्ताओं को पानी के बिल में 10 प्रतिशत तक की रियायत देने की भी योजना बनाई गई है।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बढ़ती आबादी और जल संसाधनों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए जल संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। ऐसे में वर्षा जल संचयन न केवल जल संकट का समाधान प्रस्तुत करता है, बल्कि भूजल स्तर को सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि जल संरक्षण केवल सरकारी योजना बनकर न रह जाए, बल्कि यह जनआंदोलन का रूप ले।मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने के इच्छुक लोगों को दिल्ली जल बोर्ड की ओर से तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। विशेषज्ञों द्वारा सिस्टम की स्थापना, डिजाइन और रखरखाव के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस पहल से जुड़ सकें।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 100 वर्ग मीटर या उससे बड़े भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली को अनिवार्य बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। इससे बड़े आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत परिसरों में वर्षा जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजधानी के 75 सीएम श्री स्कूलों में बड़े स्तर पर वर्षा जल संचयन की व्यवस्था विकसित की जा रही है। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 50 करोड़ लीटर वर्षा जल के संचयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में यह व्यवस्था स्थापित होने से न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि विद्यार्थियों में भी पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन के प्रति जागरूकता विकसित होगी। इससे आने वाली पीढ़ियों को जल संरक्षण के महत्व को समझने और अपनाने की प्रेरणा मिलेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के कई इलाकों में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, जिसे सुधारने के लिए वर्षा जल संचयन अत्यंत प्रभावी उपाय है। उन्होंने बताया कि लगभग 2500 वर्ग फुट की छत से वर्षभर में करीब दो लाख लीटर तक वर्षा जल का संचयन किया जा सकता है, जो भूजल पुनर्भरण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। सरकार सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों और अन्य परिसरों में भी जल संरक्षण उपायों को लागू करने पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके माध्यम से जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों से अपील की कि वे जल संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझें और वर्षा जल संचयन जैसी पहलों में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक नागरिक वर्षा जल संरक्षण की दिशा में छोटा-सा प्रयास भी करे, तो राजधानी को जल संकट से बचाने में बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार और जनता के संयुक्त प्रयासों से दिल्ली को जल-सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल और सतत विकास की दिशा में अग्रणी शहर बनाया जा सकेगा। जल संरक्षण की यह पहल न केवल वर्तमान पीढ़ी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

चाणक्यपुरी में अत्याधुनिक जिम का शिलान्यास, फिट इंडिया अभियान को मिलेगा बढ़ावा : चहल

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने शनिवार को चाणक्यपुरी स्थित पालिका सर्विसेस ऑफिसर्स इंस्टिट्यूट (पीएसओआई) क्लब, नेहरू पार्क में एक अत्याधुनिक जिम के निर्माण का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वस्थ और फिट नागरिक विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला हैं।शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए चहल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "विकसित भारत @2047" के संकल्प में शारीरिक फिटनेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया और मिशन लाइफ जैसे अभियानों के माध्यम से देश में स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। नया जिम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत लगभग 252 वर्ग मीटर क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से युक्त जिम विकसित किया जाएगा। परियोजना में भवन निर्माण, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था, वातानुकूलन (एचवीएसी), विशेष फर्श, वाटरप्रूफिंग, दरवाजे-खिड़कियां और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा।चहल ने कहा कि जिम को आधुनिक डिजाइन और उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री के साथ तैयार किया जाएगा। इसमें व्यायाम के लिए पर्याप्त स्थान, फिटनेस गतिविधियों के अनुरूप विशेष फर्श, स्वागत कक्ष तथा उपयोगकर्ताओं के लिए आकर्षक और सुविधाजनक आंतरिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।उन्होंने बताया कि लगभग दो करोड़ की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को छह माह में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परियोजना पूरी होने के बाद पीएसओआई क्लब के सदस्यों को विश्वस्तरीय फिटनेस सुविधाएं और बेहतर व्यायाम वातावरण उपलब्ध होगा।एनडीएमसी उपाध्यक्ष ने कहा कि जिम में ऊर्जा दक्ष प्रकाश व्यवस्था, उन्नत विद्युत प्रणाली, तापमान नियंत्रण और अन्य आधुनिक सुविधाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे उपयोगकर्ताओं को वर्षभर सुरक्षित और आरामदायक वातावरण मिल सके। उन्होंने विश्वास जताया कि यह नई फिटनेस सुविधा न केवल क्लब सदस्यों को लाभान्वित करेगी, बल्कि स्वास्थ्य, फिटनेस और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह परियोजना फिट इंडिया अभियान और विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

देश के शिक्षाविदों ने योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन पर "योगी के नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश" विषय पर की परिचर्चा

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिवस के पावन अवसर पर वर्चुअल माध्यम (ज़ूम)से देश के बुद्धिजीवियों द्वारा एक भव्य परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा का मुख्य विषय 'योगी के नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश' रहा, जिसमें राज्य के अभूतपूर्व विकास,सुदृढ़ कानून व्यवस्था और महिला कल्याण की योजनाएँ जैसी जन-कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से आ रहे सामाजिक बदलावों पर विचार विमर्श किया गया।

दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ बढ़ रहे उत्पीड़न को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाएगी कांग्रेस

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली: देशभर में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ बढ़ रहे उत्पीड़न को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ देशव्यापी अभियान का शंखनाद करते हुए आगामी 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विशाल विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। शनिवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग और अल्पसंख्यक विभाग के संयुक्त अधिवेशन में यह फैसला लिया गया। अधिवेशन के उपरांत कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी और अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम ने मोदी सरकार की नीतियों और नीयत पर गंभीर सवाल खड़े किए। इमरान प्रतापगढ़ी और राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि संयुक्त अधिवेशन में फैसला लिया गया है कि भाजपा सरकार के शासन में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ दोनों विभाग मिलकर देश भर में अभियान चलाएंगे। इसके तहत आगामी 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक विशाल विरोध-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इस विरोध-प्रदर्शन में देश भर से दलित और अल्पसंख्यक समाज के सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।

राजस्थान विधानसभाध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की नई दिल्ली में उप राष्ट्रपति श्री सी पी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट

» राजस्थान विधान सभा के अमृत महोत्सव के लिए किया आमंत्रित

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने शनिवार को नई दिल्ली में उप राष्ट्रपति श्री सी पी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की । विधानसभाध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी शनिवार को ही उत्तराखण्ड की पाँच दिवसीय चार धाम की यात्रा से नई दिल्ली लौटे हैं । उप राष्ट्रपति श्री सी पी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला से भेंट के दौरान विधानसभाध्यक्ष श्री देवनानी ने राजस्थान विधानसभा के 75 वें वर्ष के अमृत महोत्सव में आयोजित किए जा रहे समारोह के लिए उन्हें आमंत्रित किया जिसे दोनों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। विधानसभाध्यक्ष देवनानी ने उन्हें बताया कि अमृत महोत्सव के दौरान इस वर्ष जुलाई से अगले वर्ष मार्च में राजस्थान दिवस तक चार बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिसमें अखिल भारतीय विधायी महाकुम्भ, देश भर की महिला विधायकों का सम्मेलन,युवाओं को संसदीय शिष्टाचार से जोड़ने का कार्यक्रम तथा पूर्व एवं वर्तमान विधायकों का सम्मेलन और सम्मान समारोह के साथ ही संविधान विशेषज्ञों के विशेष सत्र आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे । विधानसभाध्यक्ष श्री देवनानी ने दोनों के साथ राजस्थान विधानसभा की 75 वर्ष की गौरव शाली यात्रा के साथ ही पिछलें दो वर्षों में राज्य विधानसभा में किए गए कई नवाचारों की जानकारी भी विस्तार से सांझा की । उन्होंने बताया कि राजस्थान विधानसभा को देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरु और श्री अटल बिहारी वाजपेयी सहित देश के कई शीर्ष नेताओं ने संबोधित किया है।

बिरसा मुंडा स्वाभिमान और सामाजिक जागरण के प्रतीक : विजेंद्र गुप्ता

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा भारत के इतिहास में एक विशिष्ट एवं प्रेरणादायी स्थान रखते हैं। 'धरती आबा' के रूप में बिरसा मुंडा केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि स्वाभिमान, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक जागरण के प्रतीक है। यह बात दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने शनिवार को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी 'भगवान बिरसा मुंडा, जनजातीय भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण एवं संग्रहालयों में उनका प्रतिनिधित्व' को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही।म्यूजियम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में संग्रहालय विशेषज्ञों, इतिहासकारों, पुरातत्वविदों, विद्वानों तथा शोधकर्ताओं ने भाग लिया। संगोष्ठी में भगवान बिरसा मुंडा की स्थायी विरासत, जनजातीय भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण तथा जनजातीय धरोहर के संरक्षण और प्रस्तुतीकरण में संग्रहालयों की भूमिका पर विचार-विमर्श किया गया।अपने संबोधन में विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि बिरसा मुंडा का आंदोलन केवल औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक संस्थाओं और स्वदेशी जीवन-पद्धति की रक्षा का एक सशक्त प्रयास भी था। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब जनजातीय समुदाय आर्थिक शोषण, सामाजिक विघटन और परंपराओं के क्षरण का सामना कर रहे थे, बिरसा मुंडा ने उनमें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक चेतना का नया संचार किया। उनके अनुसार बिरसा मुंडा से जुड़ा सांस्कृतिक पुनर्जागरण जनजातीय समुदायों में उनके इतिहास, ज्ञान-परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति विश्वास को पुनर्स्थापित करने का प्रयास था, जिसने यह सिद्ध किया कि अधिकारों की रक्षा और संस्कृति का संरक्षण परस्पर गहराई से जुड़े हुए हैं।भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत का उल्लेख करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जनजातीय समुदायों के पास मौखिक साहित्य, लोक परंपराओं, संगीत, कला, पारिस्थितिक ज्ञान और पीढ़ियों से विकसित सामाजिक व्यवहारों की अद्भुत धरोहर है। उन्होंने कहा कि ये परंपराएं केवल अतीत की स्मृतियाँ नहीं हैं, बल्कि जीवंत सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ हैं, जो आज भी भारत की सामाजिक संरचना को समृद्ध बना रही हैं।विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनजातीय समुदाय लंबे समय से वनों, जैव-विविधता और सतत जीवन-पद्धतियों के संरक्षक रहे हैं। ऐसे समय में, जब विश्व पर्यावरणीय चुनौतियों और तीव्र तकनीकी परिवर्तनों का सामना कर रहा है, उनके ज्ञान-तंत्र विशेष रूप से प्रासंगिक हो उठते हैं। उन्होंने कहा कि इन महत्वपूर्ण योगदानों के बावजूद दशकों तक अनेक जनजातीय इतिहासों और स्वतंत्रता संग्रामों को मुख्यधारा के विमर्श में पर्याप्त स्थान नहीं मिला। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने, जनजातीय गौरव दिवस मनाने और जनजातीय धरोहर के दस्तावेजीकरण के प्रयासों का स्वागत करते हुए उन्होंने इन्हें भारत के इतिहास की अधिक समावेशी समझ विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।संग्रहालयों की भूमिका पर बल देते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि संग्रहालय केवल कलाकृतियों के भंडार नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक स्मृति के संरक्षक हैं। भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रगति और तकनीकी उन्नति के साथ-साथ सांस्कृतिक आत्मविश्वास और ऐतिहासिक चेतना का विकास भी आवश्यक है।

उप महापौर ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का किया निरीक्षण, कचरा निस्तारण एवं पर्यावरणीय सुधार कार्यों की समीक्षा की

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत शनिवार को दिल्ली की उप महापौर डॉ. मोनिका पंत ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा भी उपस्थित रही। निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों ने लैंडफिल साइट पर चल रहे बायो-माइनिंग, कचरा निस्तारण, पर्यावरणीय सुधार तथा स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न कार्यों का अवलोकन किया। अधिकारियों द्वारा साइट पर संचालित गतिविधियों, कचरा प्रसंस्करण की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी भी दी गई। उप महापौर डॉ. मोनिका पंत ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि गाजीपुर लैंडफिल साइट के शीघ्र एवं प्रभावी समाधान के लिए सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निगम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। डॉ. मोनिका पंत ने कहा ने दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर लैंडफिल साइट का वैज्ञानिक एवं स्थायी समाधान निगम की प्राथमिकताओं में शामिल है। नागरिकों को बेहतर और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना निगम का संकल्प है।स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि गाजीपुर लैंडफिल साइट से जुड़े कार्यों की नियमित निगरानी की जा रही है। निगम का उद्देश्य न केवल पुराने कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण सुनिश्चित करना है, बल्कि भविष्य में कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए भी मजबूत व्यवस्था विकसित करना है। स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जनभागीदारी भी अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी क्षेत्रीय समस्याओं, स्थानीय आवश्यकताओं तथा उनके समाधान के संबंध में अपने सुझाव साझा दिए।निरीक्षण के दौरान डेम्स समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर तथा शाहदरा उत्तरी एवं शाहदरा दक्षिणी जोन के सम्मानित पार्षद उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम द्वारा 5 जून से 12 जून, 2026 तक विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 6 जून को जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित अधिकारियों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन स्थलों का भ्रमण आयोजित किया गया। जिससे उन्हें स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त 7 जून से 12 जून तक चार-स्तरीय कचरा पृथक्करण, घरेलू कम्पोस्टिंग, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण तथा विभिन्न जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

संक्षिप्त समाचार

भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा भारत के उत्तर प्रदेश की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बहन रूपा देवी ने लखनऊ कैंट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात

मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश/ भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा (भारत) के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री मति बहन रुपा देवी जी नीज निवास लखनऊ कैंट मैं एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी रहे साथ ही उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री आदरणीय श्री बृजेश पाठक जी की गरिमाई उपस्थिति में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ उक्त कार्यक्रम में हमें कार्यक्रम की अध्यक्षता करनें का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा लखनऊ के समस्त सम्मानित कार्यकर्ताओं ने हमारा जोरदार स्वागत किया! कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के महासचिव श्री अरुण कुमार वाल्मीकि जी. लखनऊ जिला अध्यक्ष श्री एडवोकेट विनय राज वाल्मीकि जी. लखनऊ मंडल अध्यक्ष श्री वाल्मीकि राहुल चौहान जी राज कमल वाल्मीकि जी. संजय कुमार वाल्मीकि जी. आदि उपस्थित रहे

किसानों को दी गई विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी

लोक तंत्र की शान , देवरिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मेगा एग्री क्रेडिट आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों एवं ग्राहकों ने भाग लिया। कैंप के दौरान कुल 258 ग्राहकों को कृषि ऋण एवं बैंक की विभिन्न कृषि योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कृषि योजनाओं के अंतर्गत कुल 32 स्वीकृति पत्र (Sanction Letter) वितरित किए गए, जिनकी कुल राशि 450 लाख रही। इससे किसानों को कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं अपनी आय में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नाबार्ड के डीडीएम सूरज प्रकाश शुक्ला जी एवं डीएमएम अरविंद कुमार जी उपस्थित रहे। बैंक की ओर से क्षेत्रीय प्रमुख जितेंद्र कुमार सिन्हा जी, लीड बैंक मैनेजर (LDM) देवरिया आर. एस. प्रेम जी तथा मुख्य प्रबंधक एएसबीडी अमित कुमार सिंह जी द्वारा उपस्थित किसानों को बैंक द्वारा संचालित विभिन्न कृषि ऋण योजनाओं, सरकारी योजनाओं एवं उनके लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।अधिकारियों ने किसानों को समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने, कृषि क्षेत्र के विकास एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु बैंक की प्रतिबद्धता को दोहराया।

ग्रामीण हुए आक्रोशित, कोटेदार के खिलाफ धरना; जांच के आदेश के बाद शांत हुआ प्रदर्शन

लोक तंत्र की शान , रुद्रपुर, देवरिया। तहसील दिवस में शनिवार को ग्राम वैदा के दर्जनों महिला-पुरुष कार्डधारकों ने कोटेदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राशन वितरण में कथित धांधली और मनमानी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने तहसील सभागार में जोरदार प्रदर्शन किया तथा कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। बाद में तहसीलदार के आश्वासन और जांच के आदेश के बाद मामला शांत हुआ।ग्रामीण महिलाओं रीना देवी, रीता देवी, मंजू देवी, उषा देवी और कविता देवी समेत अन्य कार्डधारकों ने आरोप लगाया कि गांव के कोटेदार बृजपाल द्वारा निर्धारित मात्रा से कम राशन दिया जाता है। उनका कहना था कि पहले पॉश मशीन पर अंगूठा लगवा लिया जाता है और फिर एक सप्ताह बाद राशन वितरित किया जाता है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि तौल मशीन को पर्दे के पीछे रखकर राशन की तौल की जाती है, जिससे पारदर्शिता नहीं रहती।

मथुरा : सास को 84 कोसी परिक्रमा कराने वाली बहू का हुआ भव्य स्वागत

लोक तंत्र की शान : मथुरा। आधुनिक युग में जहाँ रिश्तों में दूरियों की खबरें आम हैं, वहीं ब्रज भूमि से सेवा और समर्पण की एक ऐसी अनूठी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई भावुक हो उठा। शनिवार को 84 कोसी परिक्रमा के दौरान बहु काजल चौधरी सौख-मगोर्रा क्षेत्र के गांव पाली डूंगरा पहुंचीं। उन्होंने इस दौरान सास-बहू एकता और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। कोसीक्षेत्र की रहने वाली काजल चौधरी अपनी सास चंद्री (92) को सिर पर टब में बैठाकर बृज चौरासी कोस की परिक्रमा करा रही हैं। शनिवार को मगोर्रा क्षेत्र के पाली डूंगरा में स्थित केएम मेडीकल कॉलेज पर पहुंचने पर लोगों ने स्वागत सम्मान किया। वही केएम मेडीकल कॉलेज परिसर में ही सास बहू ने विश्राम किया। अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने वयोवृद्ध चंद्री की सेवा कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष एवं केएम हॉस्पिटल के चेयरमैन किशन चौधरी के बड़े भाई देवी सिंह (डीएम साहब) ने काजल के इस धर्मार्थ कार्य की सराहना करते हुए कहा कि आज के समय में अपनी सास को पुण्य प्राप्ति के लिए इस तरह परिक्रमा कराना बेहद दुर्लभ है। केएम परिवार काजल के इस जज्बे को नमन करता है और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएँ देता है। देवी सिंह ने यह भी बताया कि केएम मेडिकल कॉलेज द्वारा सभी 84 कोस परिक्रमार्थियों के लिए भोजन, विश्राम गृह, स्नान गृह और निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ लगातार मुहैया कराई जा रही हैं। वहीं, काजल चौधरी ने भी केएम विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रबंधन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए यहाँ की गई व्यवस्थाएँ वाकई सराहनीय हैं। इस धार्मिक और सामाजिक यात्रा के दौरान काजल चौधरी ने सास और बहुओं को विशेष संदेश दिया।

सम्पूर्ण समाधान दिवस में आई 55 शिकायतों में से मात्र 5 शिकायतों का हुआ निस्तारण

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः शासन के निर्देश पर तहसील के सभागार कक्ष में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया। आयोजित इस दिवस में राजस्व, चकबंदी, पुलिस और विकास विभाग से जुड़ी कुल 55 शिकायतें/प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। अधिकारियों ने जनसुनवाई कर 5 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया, शेष प्रकरणों के त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। समाधान दिवस में सबसे अधिक 26 शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित रहीं। इनमें पैमाइश, नामांतरण, वरासत दर्ज करने और अवैध कब्जे हटाने के मामले प्रमुख थे। चकबंदी विभाग से जुड़े 6 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें चक मार्गों पर अतिक्रमण और चकबंदी संबंधी विवाद शामिल थे। पुलिस विभाग की 8 शिकायतें मुख्य रूप से जमीनी विवाद, मारपीट और शांति भंग से जुड़ी थीं। विकास विभाग के 4 प्रकरण आवास योजना और शौचालय निर्माण से संबंधित रहे। वहीं विद्युत विभाग की 6 व अन्य विभागों की 5 शिकायतो सहित कुल 55 शिकायते प्राप्त हुई, मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्र ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का 15 दिन में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस का उद्देश्य जनता की समस्याओं का एक ही छत के नीचे समाधान करना है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राजस्व और पुलिस विभाग को संयुक्त टीम बनाकर मौका मुआयना कर विवादों का निपटारा करने के निर्देश दिए। इस दौरान एस डी एम हिमांशु उपाध्याय, पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज कुमार त्यागी, तहसीलदार लकी सिंह, नायब तहसीलदार नेहा सिंह, खंड विकास अधिकारी विजय कुमार सक्सेना आदि सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर दीदियों को नियुक्ति पत्र एवं प्रशिक्षण प्रमाणपत्र वितरित

लोक तंत्र की शान

लखनऊ। केंद्रीय योजनाओं को योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बेहतर तरीके से कार्यान्वित कर रही है। इसी क्रम में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और सोलर दीदियों के सशक्तीकरण के लिए योगी सरकार ने कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें शनिवार को प्रधानमंत्री सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत संचालित एमएनआरई सिटी एक्सीलेटर प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षित सोलर दीदियों को ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा द्वारा नियुक्ति पत्र एवं प्रशिक्षण प्रमाणपत्र वितरित किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान सोलर दीदियों को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रमाणपत्र प्रदान किए गए तथा उन्हें सौर ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों से जोड़ा गया। इस अवसर पर हनुमंत रिन्युवल कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि कंपनी चयनित सोलर दीदियों को 14,156 प्रतिमाह मानदेय प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक चयनित सोलर दीदी को कंपनी द्वारा निःशुल्क 2 किलोवाट रूफटॉप सोलर संयंत्र तथा इंडक्शन स्टोव भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे स्वच्छ ऊर्जा को अपने जीवन में अपनाने के साथ-साथ समाज में इसके प्रचार-प्रसार की प्रभावी भूमिका निभा सकें।

आज दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः हसनपुर टाउन क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के हसनपुर उपखंड कार्यालय ने बताया कि आज रविवार को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे टाउन की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उपभोक्ता अपने जरूरी विद्युत संबंधी कार्य दोपहर 12 बजे से पहले निपटा लें और पानी आदि की वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। विद्युत वितरण उपखंड प्रथम हसनपुर के एसडीओ मिथिलेश कुमार यादव,अवर अभियंता (जेई) अजय कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, निगम हित में 33/11 केवी हसनपुर टाउन उपकेंद्र पर वीसीबी यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बदलने का कार्य प्रस्तावित है। इस तकनीकी कार्य को सुरक्षित तरीके से पूरा करने के लिए शटडाउन लेना अनिवार्य है। इसी कारण दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे हसनपुर टाउन क्षेत्र की बिजली बंद रखी जाएगी। जेई अजय कुमार ने बताया कि वीसीबी उपकेंद्र का महत्वपूर्ण उपकरण है। समय के साथ इसमें खराबी आने पर पूरी आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। भविष्य में बार-बार ट्रिपिंग और बड़े फॉल्ट से बचने के लिए इसे बदलना जरूरी है। कार्य पूरा होते ही निर्धारित समय पर आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी। यदि मौसम खराब हुआ या कोई तकनीकी बाधा आई तो समय में बदलाव संभव है। कार्यालय ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली कटौती के दौरान सहयोग करें। विद्युत संबंधी जरूरी काम निपट ले और पानी का स्टोरेज पहले से कर लें।

मोहर्रम को लेकर बरेली पुलिस अलर्ट एसएसपी अनुराग आर्य ने दिए कड़े निर्देश

» पीस कमेटी बैठकें, फ्लैग मार्च, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और ड्रोन निगरानी पर रहेगा विशेष फोकस

लोक तंत्र की शान

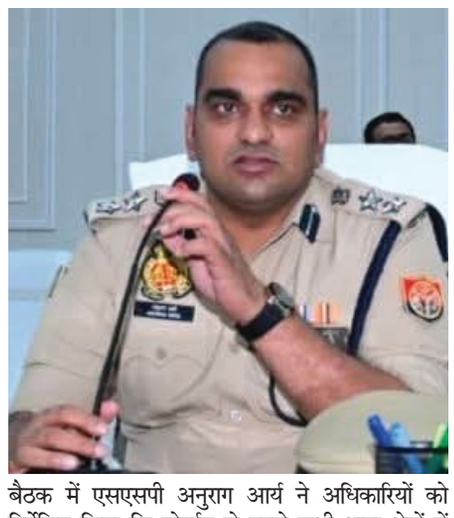

(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा) आगामी मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से बरेली पुलिस प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। इसी क्रम में शुक्रवार देर रात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने गूगल मीट के माध्यम से जिले के सभी पुलिस अधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों तथा थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। रात्रि 8 बजे आयोजित दैनिक समीक्षा गोष्ठी में जिले की वर्तमान कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति तथा मोहर्रम को लेकर की जा रही तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पर्व के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहकर निगरानी व्यवस्था बनाए रखें। बैठक में एसएसपी अनुराग आर्य ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मोहर्रम से पहले सभी थाना क्षेत्रों में पीस कमेटी की बैठकें आयोजित की जाएं। इन बैठकों में धर्मगुरुओं, ताजियादारों, आयोजकों और स्थानीय सम्मानित नागरिकों को शामिल कर आपसी संवाद और समन्वय को मजबूत किया जाए, जिससे किसी भी प्रकार की अफवाह, गलतफहमी या विवाद की संभावना को पहले ही समाप्त किया जा सके।

फर्जी लूट का हजरतनगर गढ़ी पुलिस ने किया पर्दाफाश दो घंटे में डेढ़ लाख रुपये बरामद, आरोपी गिरफ्तार

लोक तंत्र की शान

संभल/सिरसी थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी संभल के पर्यवेक्षण में थाना हजरतनगर गढ़ी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए फर्जी लूट की घटना का मात्र दो घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना से संबंधित डेढ़ लाख रुपये, एक मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर बरामद किया है। पुलिस के अनुसार 6 जून 2026 को ग्राम रहटोला निवासी मजदूर अमन पुत्र जनेपाल ने डायल-112 पर सूचना दी थी कि उसके साथ मारपीट कर डेढ़ लाख रुपये की लूट कर ली गई है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी संजय कुमार एवं चौकी प्रभारी फिरोज खान के नेतृत्व में तत्काल पुलिस टीम गठित कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को घटना संदिग्ध प्रतीत हुई। गहन पूछताछ और साक्ष्यों के विश्लेषण में सामने आया कि अमन ने अपने मालिक अवनेश कुमार पुत्र स्वर्गीय अनिल कुमार के डेढ़ लाख रुपये हड़पने की नीयत से लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना का दो घंटे के भीतर सफल अनावरण कर दिया तथा आरोपी की निशानदेही पर पूरी धनराशि बरामद कर ली। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से डेढ़ लाख रुपये नकद, एक जियो कंपनी का मोबाइल फोन तथा महिंद्रा युवराज-215 लाल रंग का ट्रैक्टर ट्रॉली सहित बरामद किया। आरोपी के विरुद्ध थाना हजरतनगर गढ़ी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेजा गया है। इस उल्लेखनीय कार्रवाई में थाना प्रभारी संजय कुमार, उपनिरीक्षक फिरोज खान, कांस्टेबल गौरव त्यागी, अक्षय कुमार तथा अनिल कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और पेशेवर जांच के चलते न केवल फर्जी घटना का खुलासा हुआ बल्कि वास्तविक तथ्य भी सामने आ गए। जनपद संभल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि झूठी सूचनाएं देकर पुलिस को गुमराह करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना हजरतनगर गढ़ी पुलिस की इस कार्रवाई की क्षेत्र में व्यापक सराहना हो रही है।

मुख्यमंत्री ने किए मां पाटेश्वरी के दर्शन

लोक तंत्र की शान

लखनऊ / बलरामपुर : गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन, पूजन-अर्चन किया। उन्होंने मां की आरती उतारी और सुखी, स्वस्थ व समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया। सीएम योगी शुक्रवार को बलरामपुर पहुंचे। यहां विकास कार्यों के लोकार्पण- शिलान्यास के बाद मंदिर में रात्रि विश्राम किया। शनिवार सुबह दर्शन-पूजन के बाद मंदिर में आये श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया। सीएम ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा व स्वच्छता की समुचित व्यवस्था का भी निर्देश दिया। स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों, संतों आदि से मुलाकात भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गोंडा के लिए प्रस्थान किया। दर्शन-पूजन के दौरान महंत मिथिलेश नाथ योगी, कालीबाड़ी गोरखपुर के महंत रविंद्र दास जी, विधायक पलटूराम, कैलाश नारायण शुक्ल आदि भी मौजूद रहे।

रामपुरः श्री खाटू श्याम जी नगर भ्रमण यात्रा धूमधाम से निकाली गयी

लोक तंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

रामपुर। उत्तर प्रदेश/ रामपुर मेंश्री खाटू श्याम जी भ्रमण यात्रा धूमधाम से निकल गई। भ्रमण यात्रा में शामिल आकर्षक झांकियों ने मन मोह लिया। शहर के कई इलाकों से होकर निकली शोभा यात्रा में श्याम बाबा की भक्ति में भक्त सराबोर हो गए। पुष्प वर्षा के बीच भक्तों ने नृत्य करते हुए बाबा के जयकारे लगाए। जगह-जगह शोभा यात्रा का स्वागत सत्कार किया गया। शुक्रवार की देर शाम कोसी मंदिर मार्ग स्थित उत्सव पैलेस से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्याम प्रेमी बाबा की भक्ति में खोकर नृत्य करते हुए चल रहे थे। आगे-आगे श्याम प्रेमी भजनों पर नृत्य कर रहे थे। शहर के बैंड धार्मिक भजनों की धुन बजाते हुए चल रहे थे। श्याम भक्त श्याम बाबा के भजनों और ढोल की थाप पर थिरकते हुए चल रहे थे। इस दौरान सभी ने जमकर जयकारे लगाए। शोभा यात्रा उत्सव पैलेस से प्रारम्भ होकर सराय गेट, थाना हजियानी, मिस्टनगंज चौराहा, जच्चा-बच्चा चौक, जामा मस्जिद, वैजनाथ हलवाई, नया गंज, गांधी समाधि, स्टार चौराहा, फैमिली चौराहा, आवास विकास, एलआईसी तिराहा, थाना सिविल लाइन्स, स्टेशन रोड, गुरूद्वारा रोड, शुगर फैक्ट्री गेट से होते हुये देर रात देर रात आदर्श रामलीला मैदान स्थित संकीर्तन स्थल पर पहुंची। शोभा यात्रा पर जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत कर श्याम प्रेमियों को जलपान और प्रसाद वितरित किया। इस दौरान समस्त श्रीश्याम भक्त परिवार के सदस्य और श्याम प्रेमी मौजूद रहे। श्रीलखदातार सेवा समिति ट्रस्ट, दुर्गा स्वीटस समेत अनेक संस्थाओं और श्याम प्रेमियों ने श्रीश्याम भ्रमण यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। भ्रमण यात्रा में शामिल भक्तों को पानी, जलजीरा, प्रसाद आदि ग्रहण कराया। जिधर से भ्रमण यात्रा निकलती श्री श्याम बाबा के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। नौ जून को सिविल लाइंस स्थित आदर्श रामलीला मैदान में श्रीश्याम संकीर्तन की धूम मचेगी। आदर्श रामलीला मैदान में होने वाले श्रीश्याम संकीर्तन महोत्सव में वृंदावन धाम से साध्वी पूर्णिमा, जयपुर से अभिषेक नामा और कोलकाता से सौरभ शर्मा श्याम बाबा का गुणगान करेंगे।

गंगेश्वरी ब्लॉक में भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक संपन्न, संगठन विस्तार और सदस्यता अभियान पर जोर

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर/रहराः शनिवार को भारतीय किसान संघ जनपद अमरोहा की विकास खंड गंगेश्वरी इकाई की मासिक व संगठनात्मक बैठक जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में ब्लॉक परिसर रहरा में आयोजित की गई। बैठक तीन सत्रों में संपन्न हुई, जिसमें संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और गांव-गांव तक जिम्मेदारी तय करने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी एवं प्रांत युवा प्रमुख संजीव कुमार शर्मा, ब्लॉक प्रभारी व उपाध्यक्ष डॉ. शिवचरण सिंह सैनी तथा जिला जैविक प्रमुख हरि प्रकाश राणा मौजूद रहे। जिला प्रभारी संजीव कुमार शर्मा का प्रवास ब्लॉक उपाध्यक्ष डॉ. कुंवर पाल सिंह राणा के आवास ग्राम सिमथला में रहा। प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी संजीव कुमार शर्मा ने संगठन के विस्तार की रूपरेखा समझाई। उन्होंने कहा कि किसान संघ को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए हर गांव तक कार्यकर्ता पहुंचे। किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान ही संगठन की पहचान है। द्वितीय सत्र में जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को पूरे खंड में सदस्यता अभियान चलाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष दिव्यांशु यादव को निर्देश दिए कि समस्त गांवों में जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की सूची शीघ्र तैयार कर जिला इकाई को सौंपी जाए, ताकि प्रत्येक गांव में संघ का प्रतिनिधि सक्रिय रहे। तृतीय सत्र में ब्लॉक प्रभारी डॉ. शिवचरण सिंह सैनी ने कहा कि ब्लॉक कार्यकारिणी के साथ जिला कार्यकारिणी के सदस्यों को भी 4 से 5 गांवों की जिम्मेदारी दी जाए। इससे निगरानी बेहतर होगी और संगठन की पकड़ मजबूत होगी। बैठक में जिला प्रचार प्रमुख अखिलेश शर्मा, ब्लॉक उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह सैनी, होमपाल सिंह, संजय सिंह, मनोज कुमार शर्मा, प्रेम सिंह सैनी, जयचंद सिंह, तेजपाल सिंह, वेदप्रकाश, हरिओम, बॉबी कुमार राणा, शीशपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक के उपरांत किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन विकास खंड अधिकारी की अनुपस्थिति में लेखाकार संजय वर्मा को सौंपा गया। ज्ञापन में फसल बीमा, खाद-बीज की उपलब्धता और गन्ना भुगतान जैसे मुद्दे शामिल थे।

संक्षिप्त समाचार

हाजीपुर में मंत्री संजय सिंह बोले- अस्पताल कर्मियों पर होगी कार्रवाई

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह ने हाजीपुर में बयान दिया है कि मुजफ्फरपुर अस्पताल में हुए अग्निकांड के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना में छह मरीजों की मौत हो गई थी। मंत्री सिंह ने कहा कि अस्पताल कर्मियों द्वारा लापरवाही बरती गई है और इसकी जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि चिराग पासवान के निर्देश पर एक टीम ने अस्पताल का दौरा किया था, जिसमें कई कमियां पाई गईं। संजय सिंह के अनुसार, अस्पताल संचालक की लापरवाही के कारण मरीजों की जान गई है। उन्होंने जोर दिया कि अस्पताल को इसकी भरपाई करनी होगी। मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि अस्पताल के कर्मचारी मरीजों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, जिससे छह लोगों की मौत हुई। उन्होंने बताया कि अस्पताल के आईसीयू में भी कई खामियां मिली हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया कि मृतकों के परिवारों को अस्पताल की ओर से अधिकतम मुआवजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी परिवार ने अस्पताल की गलती के कारण सदस्य खोया है, तो अस्पताल को इसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। मंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि अस्पताल की गहन जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी घटनाएँ दोबारा न हों।

बोलेरो से 10 बोरों में शराब बरामद, माइल चौक के पास पुलिस ने की कार्रवाई, चालक फरार

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने एक बोलेरो गाड़ी से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। यह कार्रवाई माइल चौक के पास की गई, हालांकि बोलेरो का चालक गाड़ी छोड़कर भागने में सफल रहा। उत्पाद विभाग को हाजीपुर-जंदाहा एनएच 322 से शराब ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी शुरू की। छापेमारी के दौरान पुलिस को देखकर एक बोलेरो ऊंचीडीह की ओर तेज रफ्तार से भागी। बाद में यह बोलेरो माइल चौक से हाजीपुर की तरफ मुड़कर भागने लगी। उत्पाद विभाग की टीम ने लगातार पीछा कर बोलेरो को पकड़ लिया। हालांकि, चालक गाड़ी छोड़कर कूदकर भागने में सफल रहा। बोलेरो की तलाशी लेने पर उसमें लगभग 10 बोरों में देसी शराब बरामद हुई। जब्त की गई बोलेरो का नंबर पटना का बताया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि बोलेरो की जांच पड़ताल की जा रही है और चालक और बोलेरो मालिक के विरुद्ध प्राथमिक की दर्द कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बोलेरो को बिदुपुर थाने लाया गया है। पुलिस ने चालक और मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

बीजेपी विधायक गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट में दोषी करार, राजू सिंह को हिरासत में लेने का आदेश

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिए हैं। जबकि कोर्ट ने उनकी पत्नी पत्नी रेनू सिंह, राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 (भाग 2) और आर्म्स एक्ट की धारा-30 के तहत दोषी ठहराया गया है। यह मामला 31 दिसंबर 2018 को न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई फायरिंग से जुड़ा है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में जश्न के दौरान हर्ष फायरिंग से डॉ. अर्चना गुप्ता के सिर में गोली लग गई थी। घटना के बाद फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। गंभीर रूप से घायल डॉ. अर्चना गुप्ता का इलाज चल रहा था, लेकिन 3 जनवरी 2019 को अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। 9.15 करोड़ रुपए की सालाना आय घोषित करने वाले राजू कुमार सिंह 26 फरवरी 2025 को बिहार सरकार में मंत्री थे। उनका परिवार दवा कारोबार से जुड़ा हुआ है। उनके पिता आनंदपुर खरौनी पंचायत के कई बार मुखिया रह चुके हैं। वहीं, बीजेपी विधायक राजू कुमार स्वयं चार बार अलग-अलग राजनीतिक दलों के टिकट पर विधायक चुने जा चुके हैं। उनकी पत्नी रेणु सिंह भी पूर्वी चंपारण से MLC रह चुकी हैं। राजू सिंह का जन्म 12 जनवरी 1970 को मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र स्थित आनंदपुर खरौनी गांव में हुआ था। उनकी गिनती बिहार के प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं के साथ-साथ उद्योग और व्यवसाय जगत के प्रमुख लोगों में की जाती है। कारोबारी से उद्योगपति और फिर राजनीति में कदम रखने वाले राजू सिंह पहली बार 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के टिकट पर साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। उसी साल लोजपा में टूट होने के बाद उन्होंने जनता दल (यूनाइटेड) का दामन थाम लिया। अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव में वे जदयू के टिकट पर फिर साहेबगंज से विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद 2010 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने साहेबगंज सीट से जीत दर्ज कर लगातार दूसरी बार विधायक बनने का गौरव हासिल किया।

मुजफ्फरपुर अग्निकांड में 7वीं मौत, प्रसाद हॉस्पिटल का लाइसेंस सस्पेंड

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। हादसे में झुलसे अंजनी कुमार सिंह ने शनिवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। मृतक की पहचान मुजफ्फरपुर के विशनपुर के परीं गांव के रहने वाले रामपाल सिंह के बेटे अंजनी कुमार सिंह के रूप में हुई है। फिलहाल, उनका पोस्टमार्टम एसकेएमसीएच में जारी है। अहले सुबह करीब 3 बजे पांचवीं मंजिल पर स्थित आईसीयू में भीषण आग लग गई थी। आग लगते ही अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस, प्रशासन और राहत-बचाव टीमों ने मौके पर पहुंचकर कई मरीजों को बाहर निकाला, लेकिन धुएं और आग की चपेट में आने से छह मरीजों की मौत हो गई थी। अग्निकांड के बाद ब्रह्मपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आने पर पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। हादसे के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रसाद अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। प्रशासन की ओर से अस्पताल प्रबंधन को निर्धारित समय सीमा दी गई थी। समय सीमा समाप्त होने के बाद रविवार को अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की जाएगी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। आग लगने के कारणों, सुरक्षा मानकों में हुई चूक और अस्पताल प्रबंधन की भूमिका की गहन जांच की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गोविंद हत्याकांड में सीन रीक्रिएट, खून से सना कपड़ा मिला

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के चर्चित शूटर गोविंद शर्मा हत्याकांड में पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक इस मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले गोविंद के करीबी ओंकार सिंह को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद गुरुवार को दरभंगा एयरपोर्ट से हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला और एफआईआर में नामजद बाबुल चौधरी गिरफ्तार किया गया। वहीं गुरुवार देर रात पारू थाना क्षेत्र के रहने वाले सौरभ को रक्सौल से दबोच लिया गया। शुक्रवार शाम पुलिस दोनों आरोपियों को लेकर अमर सिनेमा रोड स्थित आइकॉन टावर पहुंची और घटनास्थल पर सीन रीक्रिएट कराया। इस दौरान पूछताछ में हत्या की पूरी साजिश, रेकी और वारदात के बाद आरोपियों के भागने के तरीके का खुलासा हुआ। सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि जांच में बाबुल चौधरी इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला है। उसी ने पूरी हत्या की साजिश रची और शूटरों की व्यवस्था की। पुलिस के अनुसार बाबुल खुद गोविंद को गोली मारना चाहता था, लेकिन वारदात के समय मौके पर नहीं पहुंच सका। जांच में सामने आया है कि बाबुल ने गोविंद की हत्या की योजना कई सप्ताह पहले ही बना ली थी। उसने उसी अपार्टमेंट में, जहां गोविंद रहता था, उससे दो मंजिल ऊपर चौथी मंजिल पर कमरा किराए पर लिया था।

'फायरिंग मामले में खान सर सरेंडर नहीं करेंगे'

लोकतंत्र की शान , पटना

- वकील बोले- अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे, एफआईआर गलत, उनकी वजह से गोली नहीं चली

ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर ने पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे। उनके वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया, 'खान सर के सरेंडर करने का कोई चांस नहीं है। उन्हें बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है। मेरे क्लाइंट की वजह से फायरिंग नहीं हुई है। पुलिस ने FIR में कुछ भी लिख रखा है। खान सर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि गोली चलाओ में देख लूंगा। जमानत याचिका दायर कर रहे हैं। शनिवार को कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने का वक्त खत्म हो गया था। हम लोग सोमवार को इसे दाखिल करेंगे। खान सर के गार्ड्स प्रदीप और तारकेश्वर की जमानत के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में याचिका दाखिल की गई है। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी।'

खान सर पर हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट में FIR: टीचर पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पटना पुलिस की 5 गाड़ियां रातभर अलग-अलग वक्त पर खान सर की कोचिंग में पहुंची, लेकिन 24 घंटे बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। स्टूडेंट्स भी रातभर कोचिंग के बाहर बैठे रहे। पुलिस गाड़ी से बार-बार अनाउंस करती रही- 'हट जाइए, लौट जाइए', लेकिन स्टूडेंट्स रातभर डटे रहे। खान सर को जानने वालों का कहना है कि वो कोचिंग के अंदर ही मौजूद हैं। टीचर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया- उन्होंने हमें कहा तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ BNS की धारा 109 के तहत केस दर्ज किया है। इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है।

पुलिस की छात्रों से अपील- किसी बहकावे में न आएं: शुक्रवार को लॉ-एंड-ऑर्डर को लेकर IG ऑफिस में पुलिस की हाई लेवल मीटिंग हुई। पुलिस ने छात्रों से अपील की थी कि वो किसी कोचिंग सेंटर के बहकावे में ना आएं। दरअसल, 2 जून की रात पटना स्थित खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ था। घटना के दौरान उनके बॉडीगार्ड्स के फायरिंग किए जाने का वीडियो सामने आया था। मामले में पुलिस पहले ही दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और खान सर से भी पूछताछ की जा चुकी है। हमले वाले दिन खान सर ने पुलिस की जमकर तारीफ की थी। अब उन्होंने कहा कि पुलिस लेट पहुंची। गार्ड्स के फायरिंग वाले वीडियो पर खान सर ने कहा, मारपीट हो रही थी। मुझे पता था पुलिस को पहुंचने में समय लगेगा। पुलिस वहां उड़कर तो नहीं पहुंचती, इसलिए गार्ड्स ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की। गार्ड क्यों रखते हैं ताकि समय पड़े तो लोगों को बचा सकें। जब तक पुलिस नहीं आई थी तब तक एक बॉडीगार्ड को क्या करना चाहिए था। क्या गार्ड्स ने किसी पर फायरिंग की।

राबड़ी देवी और तेजस्वी ने अपनी सुरक्षा लौटाई सरकार के सिक्योरिटी घटाने पर नाराजगी

लोकतंत्र की शान , पटना

- बंगले के बाहर डंडे लेकर खड़े हुए कार्यकर्ता

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शनिवार सुबह अपने आवास से सारी सुरक्षा हटा दी। यहां तक की बंगले के बाहर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को भी लौटा दिया है। इसके बाद रोहिणी ने पार्टी नेताओं से राबड़ी आवास पहुंचने की अपील की। कार्यकर्ताओं का राबड़ी आवास पर जुटना शुरू हो गया है। गेट पर एक कार्यकर्ता हाथ में डंडा लिए खड़ा है। जहां कभी पुलिसकर्मी बैठते थे वहां पार्टी के नेता बैठे है। राबड़ी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी Y+ श्रेणी की सुरक्षा को वापस कर दिया है।

रोहिणी ने X पर लिखा- तमाम लालूवादियों से मेरी अपील है कि आप सब भारी संख्या में राबड़ी देवी जी के आधिकारिक आवास पहुंचकर बदले की भावना से काम रहे मुख्यमंत्री को ये सीधा , साफ और कड़ा संदेश दें कि आप सब ही लालू परिवार की असली सुरक्षा और ढाल हैं।पूरा देश, पूरा बिहार देख रहा है कि कैसे बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है और बिहार की जनता ही बदले की भावना से की गई हर कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देगी। दरअसल, 2 दिन पहले बिहार सरकार ने लालू परिवार की सुरक्षा घटा दी। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की Z+ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली थी। सरकार के इस फैसले से राबड़ी देवी नाराज थीं।

राबड़ी देवी जी और उनके परिवार को नुकसान, शारीरिक क्षति पहुंचाने की नीयत से ही ये फैसला लिया गया है। सुरक्षा में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य ही नहीं है, इसके मद्देनजर ही राबड़ी देवी जी ने अपने आधिकारिक आवास से सुरक्षाकर्मियों को वापस किए जाने का निर्णय लिया है। सम्राट सरकार को ये जान लेना चाहिए कि बिहार की करोड़ों जनता ही लालू, राबड़ी देवी जी और उनके परिवार का सुरक्षा कवच है। परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोच भी आई थी तो अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा शायद बिगड़ैल सम्राट चौधरी और उनकी सरकार को नहीं है।

कुशवाहा के बेटे दीपक का मंत्री पद से हटना तय!

लोकतंत्र की शान , पटना

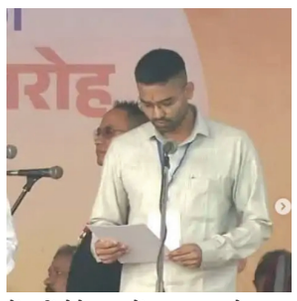

RLM नेता और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री बने रहने पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले MLC चुनाव के लिए NDA ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। जेडीयू और बीजेपी ने 4-4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की।

एक सीट पर चिराग पासवान की पार्टी LJP (R) ने अशरफ अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि, दीपक प्रकाश का नाम NDA की लिस्ट में नहीं है। इस फैसले ने पूर्व विधान पार्षद हुलास पांडेय की दावेदारी को बड़ा झटका दिया है। NDA कैंडिडेट की लिस्ट आने के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दीपक प्रकाश का नाम लिस्ट में नहीं होने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, 'ये एक सामान्य प्रक्रिया है, MLC का चुनाव हो रहा है। थोड़ा इंतजार कीजिए।' दीपक, बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, लेकिन वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। संविधान के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं होने पर उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है।

आईसीडीएस एवं मिशन शक्ति योजनाओं की समीक्षा, कमजोर प्रदर्शन पर स्पष्टीकरण तलब, प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाता: सहरसा के जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) एवं मिशन शक्ति के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त, उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क, एलएईओ, जिला परियोजना प्रबंधक (डब्ल्यूसीडीसी), जिले के सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला मिशन समन्वयक (डीएचईडब्ल्यू), जिला समन्वयक (एनएनएम), महिला पर्यवेक्षिकाएं, प्रखंड समन्वयक तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। बैठक के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) कुमारी पुष्पा ने समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों तथा प्रगति की विस्तृत जानकारी जिलाधिकारी को दी। समीक्षा के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन, पूरक पोषण आहार, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के पंजीकरण, बच्चों के नियमित वजन मापन, कुपोषण प्रबंधन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई), टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, टेक होम राशन (टीएचआर), लाभार्थियों की ई-केवाईसी, पोषण ट्रैकर ऐप पर डेटा प्रविष्टि, आंगनवाड़ी केंद्रों की आधारभूत संरचना, आभा आईडी (ABHA ID) तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचकांकों की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने आईसीडीएस के विभिन्न प्रमुख सूचकांकों का विस्तृत अवलोकन किया। जिन परियोजनाओं का प्रदर्शन जिला स्तर पर अपेक्षाकृत कमजोर पाया गया, उनके संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिन सेक्टरों में योजनाओं की प्रगति एवं उपलब्धि का प्रतिशत कम पाया गया, वहां की संबंधित महिला पर्यवेक्षिकाओं से भी स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा उन्हें अंतिम चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया गया।

मिशन शक्ति योजनाओं की समीक्षा में जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश, महिलाओं व बच्चों के हित में प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाता: सहरसा के जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को उनके कार्यालय कक्ष में महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत संचालित मिशन शक्ति योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त, उप निदेशक जनसंपर्क, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), जिला परियोजना प्रबंधक महिला एवं बाल विकास निगम, जिला मिशन समन्वयक, जिला हब फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ वीमेन तथा जिले के सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की उपलब्धियों और वर्तमान प्रगति की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने वन स्टॉप सेंटर, सहरसा को नवनिर्मित भवन में एक सप्ताह के भीतर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, ताकि महिलाओं को एक ही स्थान पर बेहतर एवं सुलभ सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। पुराना सदर अस्पताल परिसर स्थित शक्ति सदन भवन के मरम्मत कार्य की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गई। इस संबंध में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में पुलिस लाइन परिसर में संचालित पालनाघर में पेयजल समस्या का मुद्दा भी उठाया गया। इस पर जिलाधिकारी ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) को प्राथमिकता के आधार पर चापाकल स्थापित कराने का निर्देश दिया, ताकि बच्चों एवं कर्मचारियों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सके। जिलाधिकारी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना एवं सखी वार्ता कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जागरूकता कार्यक्रमों को पंचायत एवं समुदाय स्तर तक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक महिलाएं एवं बालिकाएं सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

पटना में 358 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त

लोकतंत्र की शान , पटना

- नदी थाना पुलिस ने महिला समेत 3 को दबोचा, मेन नेटवर्क की तलाश जारी

पटना जिले के नदी थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शनिवार को फतुहा एसडीपीओ-1 अवधेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि थाना क्षेत्र के पक्कीदरगाह के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडिंग कफ सिरप (नशीले सिरप) के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

एसडीपीओ अवधेश कुमार के मुताबिक, शुक्रवार, 5 जून को नदी थानाध्यक्ष सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल पक्कीदरगाह के समीप वाहन चेकिंग कर रहा था। इसी दौरान पक्कीदरगाह पीपा पुल की तरफ से एक टेम्पो (रजिस्ट्रेशन नंबर BR01PQ7456) तेज गति से आता दिखा। पुलिस को देखते ही टेम्पो सवारों ने गाड़ी को भगाकर बंकाघाट स्टेशन की ओर ले जाने का प्रयास किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीछा किया और घेराबंदी कर टेम्पो को रोक लिया। तलाशी के दौरान टेम्पो से 100 मिलीलीटर की 358 बोतल (कुल 35.800 लीटर) कोडिंग कफ सिरप बरामद की गई। पुलिस ने मौके से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल हैं।

फुलवारीशरीफ में सुलभ गैस एजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन

लोकतंत्र की शान , पटना

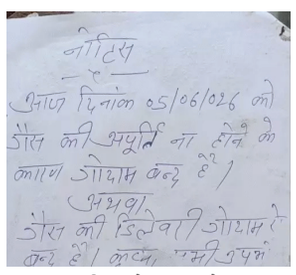

पटना के फुलवारी शरीफ स्थित नोहसा में संचालित सुलभ गैस एजेंसी के खिलाफ स्थानीय लोगों का आक्रोश लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने एजेंसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन से एजेंसी का लाइसेंस तत्काल रद्द करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे उपभोक्ताओं का आरोप है कि एजेंसी द्वारा समय पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की जा रही है। लोगों का कहना है कि गैस बुकिंग के बाद सभी औपचारिकताएं पूरी होने और मोबाइल पर डिलीवरी संबंधी संदेश आने के बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। उपभोक्ताओं के अनुसार, कई मामलों में उनके मोबाइल पर गैस डिलीवर होने का मैसेज भी भेज दिया जाता है, जबकि वास्तव में उन्हें सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जाता। स्थानीय लोगों ने एजेंसी पर गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति करने के बजाय सिलेंडरों को अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल उपभोक्ता उपेंद्र शर्मा ने बताया कि इस संबंध में पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा एजेंसी के गोदाम को दो बार सील करने की कार्रवाई की जा चुकी है। इसके बावजूद एजेंसी के कामकाज में कोई सुधार नहीं हुआ और उपभोक्ताओं की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है।

5 जिलों में आंधी-बारिश, 27 शहरों में अलर्ट, कई शहरों में छाए बादल

लोकतंत्र की शान , पटना

बिहार में उमस भरी गर्मी के बीच कई जिलों का मौसम शनिवार को बदल गया। सुबह बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार और जमुई में आंधी के साथ तेज बारिश हुई। जमुई में बिजली गिरने से 47 साल के शख्स की मौत हुई है। मुंगेर में भी एक 50 साल के किसान की जान चली गई। किसान की पहचान गणेश यादव के रूप में हुई है। मौसम विभाग ने आग प्रदेश के 12 जिलों में ऑरेंज और 15 में में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 60KMPH की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके अलावा पटना समेत दक्षिण बिहार के 11 जिलों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांक, हल्के बादल छाए रह सकते हैं। तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी।

जमुई में आकाशीय बिजली से एक शख्स की मौत: जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के कोनन इलाके में शुक्रवार देर रात आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 47 साल के महेंद्र यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

निम्न दबाव और नमी की वजह से बादल मौसम: पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी और लू जैसे हालात बने है। पूर्वी बिहार और उत्तर बिहार के कई जिलों में नमी वाली हवा चल रही है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर बने निम्न दबाव और वातावरण में बढ़ी नमी के कारण बादल बन रहे हैं और बारिश भी हो रही है। वहीं, दक्षिण और पश्चिम बिहार में गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह मानसून से पहले की गतिविधियों का प्रभाव है, जिसके कारण मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है।

बिहार में मानसून कब पहुंचेगा: दक्षिण-पश्चिम मानसून ने केरलम में दस्तक दे दी है। अब यह धीरे-धीरे देश के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ रहा है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसकी प्रगति सामान्य रही तो अगले एक से दो सप्ताह के भीतर बिहार में भी मानसून की एंट्री हो सकती है। आमतौर पर बिहार में मानसून जून के दूसरे पखवाड़े में सक्रिय होता है।

संक्षिप्त समाचार

सेमरिया के मेडिकल स्टोर में पड़ा छापा,दुकान सील अमानक एक्सपायरी दवाएं मिलीं, झोलाछाप डॉक्टर पर भी कार्रवाई

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान सीधी। जिले के सेमरिया बाजार में शनिवार शाम संयुक्त टीम ने एक मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान दुकान से अमानक और एक्सपायरी डेट की दवाएं मिलीं। साथ ही अवैध रूप से मरीजों का इलाज किए जाने का मामला भी सामने आया। टीम ने तत्काल प्रभाव से मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। यह कार्रवाई सेमरिया बाजार स्थित श्रीराम मेडिकल स्टोर पर की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के दौरान बड़ी मात्रा में एक्सपायरी और संदिग्ध दवाएं बरामद कीं। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि मेडिकल स्टोर में एक व्यक्ति झोलाछाप डॉक्टर के तौर पर मरीजों का इलाज कर रहा था और उन्हें दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन भी दे रहा था, जो नियमों का उल्लंघन है। बीएमओ डॉ. शिवेंद्र पटेल ने बताया कि विभाग को लंबे समय से क्षेत्र में अवैध दवा बिक्री और बिना अनुमति के उपचार की शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसने यह छापामार कार्रवाई की। जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रशासन ने श्रीराम मेडिकल स्टोर को तत्काल सील कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई दवाओं की विस्तृत जांच कराई जाएगी। इसके साथ ही, मेडिकल स्टोर संचालक और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक टीम के बाजार पहुंचते ही सेमरिया में अफरा-तफरी मच गई। कई मेडिकल स्टोर संचालकों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं। वहीं श्रीराम मेडिकल स्टोर का संचालक कार्रवाई की भनक लगते ही दुकान छोडक़र फरार हो गया।

बरजे से बगल से निकल गई गलत तरीके से पाईप लाईन लगाई गई वह सही तरीके से अपने घर कें पास लगाये झगड़े को तुल ना दे। नगर निगम आयुक्त ध्यान दें

लोकतंत्र कि शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश, कटनी प्राप्त विज्ञप्ति अनुसार ,जानकारी में बताया गया कि मोइन खान निवासी नगीना मस्जिद के पीछे वार्ड नंबर 6 का निवासी है और पड़ोस में असलम खान रहते हैं जो मेरे पड़ोसी हैं पड़ोसी ने एक पाइप लाइन मेरे दरवाजे के सामने और बरजे से लगे टेरी मेरी पाइप को लगा दिया जो गलत तरीके से लगा है मेरे द्वारा पड़ोसी से कहा यह पाइप लाइन गलत लगाया है आप अपने मकानके के पास अंदर लगये यह पाइप लगादेने से घर के समने खराब लगता है और पाइप लाइन से पानी कीचड़ बचता है अच्छा नहीं लगता आप इसको अपने घर के पास अंदरपाइप लाइन लगाए उसने कोई जवाब नहीं दिया कई बार बताया गया मगर षनहीं सुना बार-बार कहने के बाद भी जब ध्यान नहीं दिया तो हमने सेनगरनिगम में आवेदन दिया जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई एक हवलदार जांच करने आया था उसने भी बताया कि गलत है और चला गया उसके बाद कई दिनों तक कोई करवाई न होने से गंदगी खंभार लगाहुआ है फिर मैं 181 लगाया और सभी जगह पर शिकायत दर्ज कराई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई आए दिन झगड़ा फसाद बना रहता है नगर निगम आयुक्त से अपेक्षा है कि शीघ्र करवाई पाइपलाइन को अलग कराये जिससे यह समस्या हल हो अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना असलम खान अपनी पहुंच बताते हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारी पहुंच है इसके चलते उसके हौसले बुलंद है नगर निगम आयुक्त को चहिए इस पर शीघ्र कार्रवाई करे।

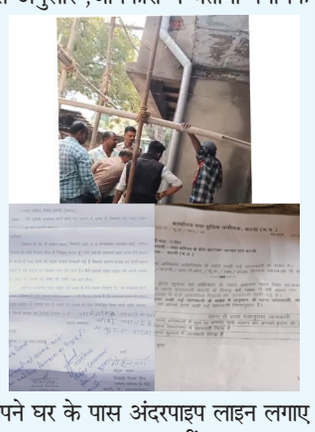

मेड़ता रोड में ओवरब्रिज निर्माण स्थल बना जलभराव का जाल,आमजन परेशान

लोकतंत्र की शान , मेड़ता रोड , एजाज़ अहमद उस्मानी। मेड़ता रोड में रेलवे गेट नंबर 101 के पास ओवरब्रिज निर्माण कार्य के चलते छोड़े गए राष्ट्रीय राजमार्ग हिस्से पर जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। पीडब्लूडी और नगर पालिका की लापरवाही के कारण यहां सड़क पर लंबे समय से पानी भरा रहने से आमजन, वाहन चालक और आसपास के व्यापारी भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, पेट्रोल पंप से आगे ओवरब्रिज निर्माण कार्य के कारण सड़क का निर्माण पूरा नहीं किया गया है, जिससे जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। इन गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने से स्थिति और भी खराब हो गई है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद कभी-कभी पीडब्लूडी और ठेकेदार द्वारा मिट्टी डाली जाती है, लेकिन वह भी कुछ ही समय में बहकर फिर से गड्ढे खुल जाते हैं। क्षेत्र में नालों की नियमित सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी निकल नहीं पाता और पूरा पानी सड़क पर ही जमा हो जाता है। इससे आए दिन वाहन फंसने की घटनाएं हो रही हैं और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है।

नागौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 टीमें बनाकर अवैध शराब पर छापेमारी

भारी मात्रा में शराब जब्त, 7 प्रकरण दर्ज

लोकतंत्र की शान

नागौर/ मेड़ता रोड , एजाज़ अहमद उस्मानी। नागौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी के निर्देशन में नागौर जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है तथा 7 अलग-अलग प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं। यह कार्रवाई जिले में 7 अलग-अलग पुलिस टीमों द्वारा की गई, जिनमें डीएसटी टीम, थाना सदर नागौर, थाना कोतवाली नागौर सहित अन्य पुलिस इकाइयों के कार्मिक शामिल रहे। अभियान का नेतृत्व वृताधिकारी जतिन जैन ने किया।

भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त–अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 2688 पव्वे अवैध देशी एवं अंग्रेजी शराब, 284 बीयर बोतलें तथा 97 बीयर कैन जब्त किए। यह कार्रवाई अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर की गई।

टीमों का गठन–इस विशेष अभियान के लिए गठित टीमों में शिवकुमार (थाना सदर नागौर), ओमप्रकाश (थाना सदर नागौर), रामकुमार (थाना सदर नागौर), पुरखाराम (AHTU), विक्रम सिंह (थाना कोतवाली नागौर), गजेन्द्र सिंह (कोतवाली नागौर) एवं जगदीश कूड़ी सहित अन्य पुलिस कार्मिक शामिल रहे।

आरोपियों पर कार्रवाई–पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान कई आरोपियों के कब्जे से अवैध शराब बरामद की गई, जिनमें विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग ब्रांड की देशी व अंग्रेजी शराब, बीयर बोतलें एवं कैन शामिल हैं। सभी मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस की सख्त चेतावनी–पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के कारोबार पर लगातार सख्त निगरानी रखी जा रही है और ऐसे मामलों में आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। इस पूरे अभियान के दौरान पुलिस की सात अलग-अलग टीमों ने समन्वित रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध शराब कारोबार पर बड़ा प्रहार किया है।

मेड़ता रोड में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, मौसम हुआ सुहावना

दिनभर की तपिश से मिली राहत

लोकतंत्र की शान

मेड़ता रोड , एजाज़ अहमद उस्मानी। मेड़ता रोड क्षेत्र में शनिवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली। दिनभर तेज़ धूप और उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को शाम करीब सात बजे हुई बारिश ने बड़ी राहत दी। बारिश शुरू होने से पहले तेज़ हवाओं का दौर चला, जिससे वातावरण में धूल उड़ती नजर आई और मौसम में ठंडक घुलने लगी। तेज़ हवाओं के चलते कुछ देर तक हालात सामान्य से अलग हो गए। इसके बाद हल्की से मध्यम बारिश शुरू हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया। दिनभर की भीषण तपिश और उमस से परेशान लोगों के चेहरे पर बारिश के बाद राहत साफ देखी गई। हालांकि बारिश और हवाओं के साथ ही बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई, जिससे कई इलाकों में अंधेरा छा गया। बिजली गुल होने से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा, लेकिन बारिश के कारण मौसम ठंडा होने से गर्मी का असर काफी हद तक कम हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, लंबे समय बाद शाम के समय इस तरह की मौसमीय गतिविधि देखने को मिली, जिससे तापमान में गिरावट आई और रात का मौसम काफी सुहावना हो गया।

बढते प्रदूषण की रोकथाम हेतु वृक्षारोपण एक प्रमुख घटकः भदौरिया

» पर्यावरण दिवस के अवसर पर सव्यसॉची सेंटर द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सीधी जिले के सामाजिक अशासकीय संगठन सव्यसांची सेंटर सीधी एवं भोपाल के प्रतिष्ठित साइकिल संगठन वाह गुरुप के संयुक्त तत्वाधान में झील की खूबसूरत नगरी भोपाल में प्लास्टिक एवं प्रदूषण मुक्त शहर में स्थित खूबसूरत कालिया सोत डेम के आसपास प्लाष्टिक एवं प्रदूषण फैला रहे कचरे को इक्ठ्ठा कर निमग को सौपा गया। कार्यक्रम के दौरान घूमने आए हुए आसपास के पर्यटक कार्यक्रम से प्रभावित होकर सहभागी बने एवं संकल्प लिया कि खाने.पीने के लिए लाए हुए थैले, प्लास्टिक की बोतल अथवा अन्य प्रदूषण फैलाने वाली चीजो को यहां नहीं फेकेगे तथा इस हेतु लोगो को जागरूक भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान अशासकीय संस्था सव्यसॉची सेंटर के सचिव संजय भदौरिया ने लोगो से शहर को प्लाष्टिक मुक्त, जल संचय, सौर ऊर्जा अपनाने और धरती को पेड़ दो, पृथ्वी बचाओं नारा देते हुऐ लोगों से अपील की और कहा कि पौधे चाहे घर के गमले में ही लगावे किंतु हर

घर में पौधे जरूर लगावें। कार्यक्रम के उपरांत उपस्थित सभी सदस्यों ने नीम, बेल, टिकोमा जैसे पौधों का रोपण किया। कार्यक्रम के दौरान सीनियर साइंटिस्ट डॉ. पुनीत चंद्रा, उप प्राचार्य डॉ. बीएस भदौरिया, वीएनएस कॉलेज के प्रो. डॉ. राजू खनाडे, कैप्टन यस जहांगीर, असिस्टेंट प्रो. पवन मालवी फिजिकल एजुकेशन बीएमएस कॉलेज, स्थानीय व्यवसायी विकास सेठ, हर्ष सिंह के साथ अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

अधजली अवस्था में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी, पुलिस अधीक्षक ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के बहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुअरा कला में एक अज्ञात महिला का अधजली अवस्था में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही बहरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका की आयु लगभग 20 से 30 वर्ष के बीच प्रतीत हो रही है। महिला के माथे पर बिंदी एवं कानों में बाली पहनी हुई मिली है। शव की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सीधी श्री संतोष कोरी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर मामले की जानकारी ली। उन्होंने थाना प्रभारी बहरी को मृतका की शीघ्र पहचान स्थापित करने, सभी संभावित पहलुओं से जांच करने तथा घटना में संलिप्त व्यक्तियों की जल्द पहचान एवं गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस द्वारा मौके से आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए हैं तथा मामले की गहन विवेचना की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। सीधी पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त महिला की पहचान अथवा उसके संबंध में कोई जानकारी हो तो तत्काल थाना बहरी या निकटतम पुलिस थाना में सूचना दें। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही घटना का खुलासा किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।

एफआईआर नहीं हुई तो होगा उग्र आंदोलनः विक्रांत पेपर लीक कांड पर एनएसयूआई ने कॉलेज प्रशासन को घेरा

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। शासकीय स्वशासी संजय गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सामने आए पेपर लीक प्रकरण को लेकर शनिवार को एनएसयूआई ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव विक्रांत सिंह परिहार के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने कॉलेज परिसर पहुंचकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच, दोषियों पर एफआईआर तथा कठोर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि 3 जून 2026 को आयोजित बीए एवं बीकॉम तृतीय वर्ष की इंग्लिश लैंग्वेज एवं कम्युनिकेशन स्किल विषय की परीक्षा का प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। जिसके बाद परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। छात्रों का कहना है कि यह केवल पेपर लीक नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर हमला है। ज्ञापन में परीक्षा नियंत्रक एवं परीक्षा समिति को जांच पूर्ण होने तक निलंबित करने, वर्तमान परीक्षा समिति को भंग कर नई समिति गठित करने, प्रश्नपत्र निर्माण एवं वितरण प्रक्रिया की जांच कराने तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी की गई है। एनएसयूआई प्रदेश सचिव विक्रांत सिंह परिहार ने कहा

कि स्वशासी प्रकोष्ठ की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि संबंधित प्रश्नपत्र से जुड़ी सामग्री कामर्श होरिजोन नामक यूट्यूब चैनल पर पहले से उपलब्ध थी। ऐसे में प्रश्नपत्र तैयार करने वाले और इस पूरी प्रक्रिया में शामिल लोगों की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा दी जाए। विक्रांत परिहार ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सात दिनों के भीतर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और दोषियों पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो एनएसयूआई व्यापक छात्र आंदोलन छेड़ेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी। प्रदर्शन के दौरान लगभग 200 से अधिक छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। स्थिति को देखते हुए कॉलेज परिसर में सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। छात्रों ने परीक्षा समिति को भंग करने, जिम्मेदार अधिकारियों को हटाने तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग उठाई। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य प्रभाकर सिंह ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक होने की जानकारी मिलने के बाद संबंधित परीक्षा को तत्काल निरस्त कर दिया गया था। मामले की सूचना वरिष्ठ कार्यालय को भेज दी गई है और जांच प्रक्रिया जारी है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

बायो-माइनिंग परियोजना का शुभारंभ

विधायक जगमोहन आनंद संग किया निरीक्षण

अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश

लोकतंत्र की शान, राजेंद्र करनाल की रिपोर्ट

करनाल। स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त करनाल के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए महापौर रेणु बाला गुप्ता ने करनाल-मेरठ रोड स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्लूएम) साइट पर बहुप्रतीक्षित लीगेसी वेस्ट रिमेडिएशन (बायो-माइनिंग) परियोजना का विधिवत शुभारंभ किया। यह महत्वाकांक्षी परियोजना वर्षों से एकत्रित पुराने कचरे के वैज्ञानिक एवं पर्यावरण-अनुकूल निस्तारण के माध्यम से बेशकीमती भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण को सशक्त करने की दिशा में युगांतकारी कदम साबित होगी। इस ऐतिहासिक शुरुआत के अवसर पर महापौर रेणु बाला गुप्ता ने करनाल के विधायक जगमोहन आनंद के साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट का गहनतापूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने यहां चल रहे विविध कार्यों का बेहद बारीकी के साथ विस्तृत जायजा लिया और मौके पर मौजूद संबंधित उच्चाधिकारियों व तकनीकी टीम के साथ परियोजना की प्रगति, कार्यप्रणाली एवं निर्धारित लक्ष्यों पर विस्तार से रोडमैप तैयार किया।

बाजार से रुई-पट्टी लाने पर प्लास्टर कराने की मजबूरी

» अव्यवस्थाओं से साए में जिला अस्पताल सीधी

» प्लास्टर कराने चक्कर काटते हैं गरीब मरीज

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। कुछ डॉक्टर पैसे की हवस में अपना सेवा का दायित्व भूलकर मरीज को ज्यादा से ज्यादा परेशान करने को ही अपना सेवा भाव मान चुके हैं। ऐसा ही हाल जिला अस्पताल सीधी का बना हुआ है। मरीजों की शिकायत पर जब आज सुबह 10 बजे जायजा लिया गया तो आउटडोर के समीप संचालित ड्रेसिंग रूम में प्लास्टर कराने के लिए मरीजों की भीड़ जमा थी। किंतु ड्रेसर कक्ष से गायब थे। मरीज ड्रेसरों को तलाशने में इधर-उधर भटकने को मजबूर थे लेकिन कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। करीब 11 बजे तीन कर्मचारी कक्ष में एक साथ पहुंचे और उनके द्वारा सभी मरीजों को बाहर बैठने के लिए कहा गया। जिनको प्लास्टर लगना था उनसे साफतौर पर कहा गया कि बाजार से रुई एवं पट्टी लाएं तभी हो पाएगा। कुछ मरीजों के परिजनों ने जब कहा कि सरकारी अस्पताल में पट्टी और रुई का अकाल पड़ गया है तो उनका कहना था कि जब उन्हें अस्पताल के स्टोर से नहीं मिलता तो वह क्या करें। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत डॉ. केबी प्रजापति अस्थि रोग विशेषज्ञ से की तो उनका साफ कहना था कि बाजार से रुई-पट्टी लानी पड़ेगी। वहीं कुछ मरीजों एवं उनके परिजनों का कहना था कि ड्रेसिंग रूम में ड्यूटी करने वाले कर्मचारी सुविधा शुल्क की मांग करते हैं जो उनको सुविधा शुल्क देते हैं उनको अस्पताल की ओर से प्लास्टर कर दिया जाता है। इसी तरह पट्टी करवाने एवं प्लास्टर कटवाने के लिए भी यहां मौजूद कर्मचारी सुविधा शुल्क की मांग करते हैं। जो मरीज प्लास्टर कटवाने के लिए सुविधा शुल्क नहीं देता उसको घंटों कक्ष के बाहर बैठने के लिए मजबूर करते हैं। उधर अस्पताल सूत्रों का कहना था कि इस तरह का रवैया काफी समय से चल रहा है। जिसको देखने वाला कोई नहीं है। यदि जिला अस्पताल में इस तरह की अव्यवस्था है तो अन्य सरकारी अस्पतालों का भगवान ही मालिक है।

कटनी में औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाईः 10 मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ नोटिस जारी

» संतोषजनक जवाब नहीं तो लाइसेंस होंगे निलंबित

लोकतंत्र किशान हसन रशीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी। जिले में औषधियों की बिक्री और भंडारण व्यवस्था को नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्री आशीष तिवारी द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में औषधि प्रशासन विभाग ने मेडिकल स्टोर्स की जांच के बाद अनियमितता और कमियां पाये जाने पर सख्त कार्रवाई करते हुए जिले के 10 मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर श्री तिवारी के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया और इस औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा नियमावली, 1945 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन एवं अन्य अनियमितताएं पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई है।संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई की जायेगी।

ये मिलीं कमियां–ड्रग इंस्पेक्टर सोनम जैन ने बताया कि मेडिकल स्टोर्स की जांच में दवाओं की बिक्री केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की निगरानी में की जानी चाहिए थी, लेकिन कई स्टोर में वे नहीं मिले।उचित बिल या कैश मेमो ग्राहकों को देना आवश्ययक है, जो भी कई स्टोर में नहीं मिले।अनुसूची एच, एच 1 एवं एक्स दवाओं की बिक्री केवल अधिकृत चिकित्सक के वैध प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जा सकता है तथा निर्धारित अभिलेख संधारित करना अनिवार्य है। लेकिन अभिलेख संधारित नहीं मिले।दवाओं की खरीद एवं बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड भी संधारित होना चाहिए था।

इन मेडिकल स्टोर्स को जारी हुआ नोटिस–कारण बताओ नोटिस जिन मेडिकल स्टोर्स को जारी किए गए हैं उनमें साईं मेडिकल एंड जनरल स्टोर हरदुआ, नवीन मेडिकल स्टोर रीठी, अनिका मेडिकल एंड जनरल स्टोर देवगांव, संदीप मेडिकल स्टोर बहोरीबंद, प्रकाश मेडिकल, आदित्य मेडिकल बहोरीबंद, गौतम मेडिकल, गणेश मेडिकल, मोहित मेडिकल एंड जनरल स्टोर पिपरोंध तथा माहिर मेडिकल एंड जनरल स्टोर निवार पहाड़ी शामिल हैं। औषधि प्रशासन विभाग द्वारा संबंधित संचालकों से निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि प्राप्त जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो संबंधित मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध लाइसेंस निलंबन अथवा निरस्तीकरण जैसी कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के प्रति रहेगा आभारीः शहबाज शरीफ

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें एक शांतिप्रिय व्यक्ति बताया है। शरीफ ने कहा कि भारत के साथ सैन्य संघर्ष को खत्म कराने में राष्ट्रपति ट्रंप के समय पर किए गए हस्तक्षेप के लिए पाकिस्तान हमेशा उनका आभारी रहेगा। अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक विशेष समारोह में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अमेरिका और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को लगभग आठ दशकों से जारी एक सच्चा और खास रिश्ता करार दिया। शहबाज शरीफ ने पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले का जिक्र किया, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों तक गंभीर सैन्य संघर्ष चला था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने दावा किया कि पहलगाम घटना के बाद भारत की आक्रामकता को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने समय रहते निर्णायक भूमिका निभाई, जिसके कारण पिछले साल 10 मई को दोनों देशों के बीच जारी सैन्य संघर्ष पूरी तरह थम सका। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति बहाल करने और लाखों लोगों की जान बचाने के लिए ट्रंप को हमेशा याद किया जाएगा। गौरतलब है कि पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने पिछले साल सात मई को ऑपरेशन सिंदूरशुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में सक्रिय आतंकी ढांचे को ध्वस्त करना था। हालांकि, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान इस मामले में अमेरिकी मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत का रुख इस पर हमेशा से अलग रहा है। भारत लगातार यह कहता आया है कि दोनों देशों के बीच हुआ समझौता पूरी तरह द्विपक्षीय था और उसने किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के दावों को साफ तौर पर खारिज किया है। प्रधानमंत्री शरीफ ने ट्रंप के अद्वितीय और साहसी नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी फैसलों से अमेरिका वैश्विक स्तर पर शांति और समृद्धि को आगे बढ़ा रहा है। इतिहास को याद करते हुए उन्होंने कहा कि 1947 में पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद उसे मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में अमेरिका शामिल था। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान इस समय अमेरिका और ईरान के बीच संपर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मॉरीशस में कांगो, युगांडा या दक्षिण सुडान से आने वाले विदेशी नागरिकों पर बैन

पोर्ट लुई। इबोला वायरस प्रकोप को देखते हुए मॉरीशस सरकार ने उन विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी है जिन्होंने पिछले 21 दिनों में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, युगांडा या दक्षिण सुडान की यात्रा की है, वहां से होकर गुजरे हैं या वहां ठहरे हैं। हालांकि, मॉरीशस के नागरिकों और वैध वर्क परमिट, रेजिडेंस परमिट, बिजनेस परमिट या स्टूडेंट परमिट रखने वाले विदेशियों को देश में प्रवेश की अनुमति रहेगी, लेकिन यदि उन्होंने पिछले 21 दिनों में इन तीन देशों का दौरा किया है, तो उन्हें 21 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। मीडिया रिपोर्ट में अफ्रीकन यूनियन के मुताबिक कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान में फैला इबोला संक्रमण क्षेत्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। मॉरीशस सरकार ने यह भी कहा है कि प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट और अन्य प्रवेश की जगह पर विशेष स्वास्थ्य जांच और जोखिम मूल्यांकन किया जाएगा। यदि किसी यात्री में इबोला के लक्षण पाए जाते हैं, तो उसे आइसोलेट कर चिकित्सकीय जांच की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने जुलाई में मॉरीशस में आयोजित होने वाले 18वें यूएस-अफ्रीका बिजनेस समिट को भी फिलहाल स्थगित करने का अनुरोध किया है। 15 मई को कांगो और युगांडा में इबोला प्रकोप की आधिकारिक घोषणा की गई थी। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और डब्ल्यूएचओ ने पूरे अफ्रीका के लिए इबोला तैयारी और प्रतिक्रिया योजना शुरू की। इस योजना के तहत जून से नवंबर तक के लिए 51.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाने का लक्ष्य है, ताकि अफ्रीकी देशों को संक्रमण की पहचान, रोकथाम और त्वरित प्रतिक्रिया में मदद मिल सके। इन दोनों संस्थाओं के मुताबिक अब तक 34 स्वास्थ्यकर्मी इबोला वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 7 की मौत हो चुकी है, जबकि 6 स्वस्थ हो चुके हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि इस प्रकोप से निपटने में कई चुनौतियां सामने हैं। इनमें बुनदिबुग्यो इबोला स्ट्रेन के लिए प्रभावी चिकित्सा संसाधनों की कमी, कमजोर स्वास्थ्य ढांचा, सीमित संसाधन, लोगों की ज्यादा आवाजाही, असुरक्षा, विस्थापन, स्वास्थ्यकर्मियों का संक्रमित होना और गलत सूचनाओं का फैलना हैं।

कोंकण के दक्षिणी हिस्से में मानसून की दस्तक, जल्द पूरे महाराष्ट्र में पहुंचेगा

मुंबई। महाराष्ट्रवासियों का मानसून को लेकर इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। शनिवार को मानसून ने दक्षिण कोंकण के रास्ते महाराष्ट्र में प्रवेश कर लिया। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मानसून की आगे की प्रगति के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल हैं और जल्द ही यह मुंबई सहित राज्य के अन्य हिस्सों में भी पहुंच सकता है। इससे भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के कुछ इलाकों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मानसून के आगे पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य समय से तीन दिन देरी से, यानी 4 जून को केरल पहुंचा था। इसके बाद यह तेजी से उत्तर दिशा की ओर बढ़ा और 5 जून को कर्नाटक, तमिलनाडु तथा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। इसी दौरान मानसून अरब सागर के कुछ हिस्सों और गोवा के कई क्षेत्रों तक भी पहुंच गया था, जिससे महाराष्ट्र में इसके जल्द प्रवेश की संभावना जताई जा रही थी। इसी क्रम में शनिवार को मानसून ने पूरे गोवा क्षेत्र को कवर करते हुए महाराष्ट्र के दक्षिण कोंकण में दस्तक दे दी है। पिछले कुछ सप्ताहों से राज्य के कई हिस्से, विशेषकर विदर्भ, भीषण गर्मी और लू जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। बीच-बीच में हुई आंधी और बारिश से लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन सभी की निगाहें मानसून के आगमन पर टिकी थीं। अब मानसून के राज्य में प्रवेश करने के बाद अगले कुछ दिनों में इसके पूरे महाराष्ट्र में फैलने का अनुमान है। आमतौर पर दक्षिण कोंकण में पहुंचने के बाद मानसून तेजी से आगे बढ़ते हुए मुंबई और उत्तर कोंकण तक पहुंच जाता है। इसलिए मुंबई में भी जल्द मानसून के आगमन की संभावना जताई जा रही है।

दिल्ली-एनसीआर में उमस, दक्षिण-पश्चिम मानसून देश के कई राज्यों में बढ़ा आगे

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर में हल्की से मध्यम वर्षा होने से तापमान में आई गिरावट के बाद, शुक्रवार को एकबार फिर उमस और भीषण गर्मी बढ़ने से निवासी बेहाल रहे। वहीं, दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से देश के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार राजधानी में रविवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। यहां का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 38-40 डिग्री सेल्सियस और 26-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं, आठ जून को आसमान साफ रहेगा। इस दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 39-41 डिग्री सेल्सियस और 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। नौ जून को भी मुख्य रूप से आसमान साफ़ रहेगा। इस दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 40-42 डिग्री सेल्सियस और 28-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम अधिकारियों के मुताबिक, आज दक्षिण-पश्चिम मानसून महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, गोवा के बाकी हिस्सों, कर्नाटक के कुछ और हिस्सों, तमिलनाडु के अधिकतर हिस्सों और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। अगले 7 दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत में कहीं-कहीं 7-20 सेमी तक भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, पूर्वी भारत, उत्तर-पश्चिम भारत और मध्य एशिया के अलग-अलग क्षेत्रों में अगले छह दिनों के दौरान कहीं पर हल्की बारिश और कहीं पर भारी बारिश होने के आसार हैं।

'मेरा भारत युवा सम्मेलन' विविध प्रतिभा व असीम क्षमता का सशक्त प्रतिबिंब बना

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को त्यागराज स्टेडियम में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित 'विकसित भारत के लिए युवा - मेरा भारत युवा सम्मेलन' में शामिल हुईं। देशभर से आए 6,000 से अधिक युवाओं की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, युवा मामलों की सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित रहीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमियों, खिलाड़ियों, कलाकारों, कंटेंट क्रिएटर्स, यूपीएससी अभ्यर्थियों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का यह मंच वास्तव में भारत की युवा शक्ति का उत्सव है। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के इतने प्रतिभाशाली युवा और प्रेरणास्रोत व्यक्तित्वों की उपस्थिति इस आयोजन को वास्तव में 'तारे जमीन पर' जैसा स्वरूप देती है। जब एक ही मंच पर युवा उद्यमी, खिलाड़ी, कलाकार, जनप्रतिनिधि, कंटेंट क्रिएटर्स और यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले युवा उपस्थित हों तो यह भारत की विविध प्रतिभा और असीम क्षमता का सशक्त प्रतिबिंब बन जाता है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया को इस अभिनव पहल के लिए बधाई देते हुए कहा कि मेरा भारत युवा सम्मेलन युवाओं को सम्मानित करने के साथ-साथ उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत का युवा देश की जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा आबादी है, जो मेहनती, दूरदर्शी, रचनात्मक और साहसी है। खेल, उद्यमिता, कला, तकनीक, कंटेंट निर्माण, शिक्षा और प्रशासन जैसे हर क्षेत्र में भारतीय युवाओं ने नए मानदंड स्थापित किए हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता के पीछे अथक परिश्रम, अनुशासन और समर्पण होता है। यही समर्पण भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है।

मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि अगर देश का प्रत्येक युवा एक कदम आगे बढ़ाता है, तो 140 करोड़ भारतीयों का देश भी उसी गति से आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित भारत-2047' के संकल्प को साकार करने में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने युवाओं से अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और इनोवेशन की क्षमता को राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित करने का आह्वान करते हुए कहा कि जीवन में देश के लिए मरने का अवसर मिले या न मिले, लेकिन देश के लिए जीने और योगदान देने का अवसर हम सभी के पास है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत की युवा शक्ति ही 'विकसित भारत-2047' का सबसे मजबूत आधार बनेगी।

जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ जवान समेत दो हिरासत में, राइफल व 50 कारतूस बरामद

एजेंसी, बारामुला

जम्मू-कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने कनिस्पोरा क्षेत्र में देर रात नाका चेकिंग के दौरान एक कार को रोककर दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से एक 12-बोर राइफल और 50 कारतूस बरामद किए गए।

पुलिस के अनुसार, कनिस्पोरा-जाहामा क्रॉसिंग पर एसओजी बारामूला और 52 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) की संयुक्त टीम द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान जम्मू पंजीकरण संख्या जेके02डीएन-6527 वाली एक बलेनो कार को रोका गया। वाहन में सवार दो व्यक्तियों की पहचान सिकंदर खान (32) पुत्र नजीर अहमद खान निवासी गिंगल उरी तथा वकील अहमद ठाकरी (40) पुत्र नूरदीन ठाकरी निवासी कमलकोट उरी के रूप में हुई।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वकील अहमद ठाकरी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में जवान के पद पर कार्यरत हैं। वह पहले 218 बटालियन, छत्तीसगढ़ में तैनात थे और हाल ही में उनका स्थानांतरण 237 बटालियन, राजस्थान में हुआ था। हालांकि, उन्होंने अभी तक नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। वहीं, सिकंदर खान स्थानीय निवासी है। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि दोनों आरोपित पिछले दो दिनों से वाहन लेकर इलाके में घूम रहे थे।

चेकिंग के दौरान वाहन और उसमें सवार व्यक्तियों की तलाशी लेने पर एक 12-बोर राइफल और 50 कारतूस बरामद किए गए। मौके पर मौजूद टीम ने मामले की सूचना एसएचओ बारामूला को दी, जिसके बाद दोनों व्यक्तियों को पूछताछ के लिए जीआईसी बारामूला लाया गया। बाद में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें बारामूला पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया।

जांच के दौरान यह सामने आया कि बरामद 12-बोर राइफल वकील अहमद ठाकरी के नाम पर लाइसेंसी हथियार है, जिसे उन्होंने 5 जून, 2026 को गंग्याल, जम्मू से खरीदा था। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

भाजपा उम्मीदवार तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने दाखिल किया नामांकन

एजेंसी, भोपाल

मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दोनों उम्मीदवार तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने शनिवार को दोपहर में विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की रिक्त तीन सीटों के लिए आगामी 18 जून को मतदान होना है। भाजपा ने दो सीटों के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा के दोनों उम्मीदवार शनिवार को दोपहर करीब 12:30 बजे विधानसभा पहुंचे और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत समेत अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं व जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी विधायकों की एक बैठक हुई। इसमें दोनों उम्मीदवारों तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल के अलावा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में चुनाव की रणनीति और एकजुटता को लेकर चर्चा हुई। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और दोनों उम्मीदवार भाजपा कार्यालय परिसर में स्थित शिव और हनुमान मंदिर पहुंचे। वहां नेताओं ने जीत के लिए पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इसके बाद करीब 15 से ज्यादा कारों के भारी काफिले के साथ सभी नेता विधानसभा के लिए रवाना हुए।

समुद्र में मछली पकड़ने गए तीन मछुआरे लापता तटरक्षक बल ने शुरू किया खोज अभियान

एजेंसी, कडलूर

तमिलनाडु के कडलूर और पुडुचेरी से समुद्र में मछली पकड़ने गए तीन मछुआरों के लापता होने से तटीय क्षेत्रों में चिंता का माहौल है। कई दिनों से उनका कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी सुरक्षित तलाश और शीघ्र वापसी की मांग को लेकर शनिवार को सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। घटना के बाद भारतीय तटरक्षक बल, मत्स्य विभाग और अन्य एजेंसियां खोज एवं बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। दरअसल, कडलूर जिले के तटीय इलाकों में बड़ी संख्या में मछुआरा समुदाय निवास करता है और यहां के अधिकांश परिवारों की आजीविका समुद्री मत्स्य व्यवसाय पर निर्भर है। स्थानीय मछुआरे प्रतिदिन मोटरबोट, कट्टूमरम और फाइबर नौकाओं के जरिए समुद्र में जाकर मछली पकड़ते हैं।

वर्तमान में तमिलनाडु में वार्षिक मत्स्य प्रतिबंध अवधि लागू है, जिसके कारण मोटरबोट के माध्यम से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं है। लेकिन इसी दौरान कडलूर जिले के सी. पुदुपेट्टई शन्मुगा नगर निवासी रवि उर्फ रमेश (28), मनोहर (27) तथा पुडुचेरी के अनाथा सिद्दीक कुलम क्षेत्र निवासी नागवेल (40) गत 2 जून को दोपहर करीब 2:30 बजे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में निकले थे। तीनों मछुआरे इंद्रानगर निवासी वीरवेल की फाइबर नाव से समुद्र में रवाना हुए थे। सामान्य परिस्थितियों में उन्हें 3 जून तक तट पर लौट आना चाहिए था, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद उनके वापस नहीं आने से परिजनों की चिंता बढ़ गई।

मछुआरों का कोई संपर्क नहीं होने पर स्थानीय समुदाय ने भी अपने स्तर पर खोज अभियान शुरू किया। कई मछुआरे नौकाओं के जरिए समुद्र में उनकी तलाश के लिए निकले, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद उनका कोई पता नहीं चल सका। इससे नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने परंगीपेट्टई के निकट अन्नंगोविल क्षेत्र में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि खोज अभियान को और तेज किया जाए तथा सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर लापता मछुआरों का जल्द से जल्द पता लगाया जाए।

सूचना मिलने पर मत्स्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मछुआरों की तलाश के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र में व्यापक खोज एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया है। समुद्र के विभिन्न हिस्सों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और संभावित समुद्री मार्गों की भी निगरानी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार खोज अभियान लगातार जारी है। हालांकि, स्थानीय ग्रामीणों और मछुआरा संगठनों ने मांग की है कि खोज अभियान में हेलीकॉप्टर को भी शामिल किया जाए। उनका कहना है कि हवाई निगरानी के जरिए समुद्र के बड़े क्षेत्र को कम समय में खंगाला जा सकता है, जिससे मछुआरों का जल्द पता लगाने में मदद मिलेगी।

अब बुलेट ट्रेन परियोजना से भी जुड़ेगा पश्चिम बंगाल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुभेंदु संग की बैठक

एजेंसी, कोलकाता

पश्चिम बंगाल के राज्य सचिवालय नबान्न में शनिवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में राज्य में रेल परियोजनाओं के विस्तार, मेट्रो विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक से पहले दोनों पक्षों ने संयुक्त पत्रकार वार्ता भी की, जिसमें रेल मंत्री ने पश्चिम बंगाल में चल रही और प्रस्तावित रेल परियोजनाओं को लेकर विस्तृत जानकारी दी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्व की सरकारों के समय रेल परियोजनाओं को लेकर कई बार अनुमति मिलने में देरी होती थी और कुछ मामलों में काम न्यायालय तक पहुंच जाता था, जिससे परियोजनाओं की गति प्रभावित होती थी। उन्होंने चिंगड़ीघाटा मेट्रो परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय कई अड़चनें आई थीं, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं और केंद्र व राज्य के बीच बेहतर समन्वय से परियोजनाओं को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल में विकास कार्यों के लिए अनुकूल माहौल बना है और इससे रेल क्षेत्र में भी तेजी आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में दिल्ली से सिलिगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है, जिससे यह दूरी लगभग छह घंटे में पूरी की जा सकेगी। प्रस्तावित मार्ग दिल्ली से लखनऊ और पटना होते हुए सिलिगुड़ी को जोड़ेगा, जिससे पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। इस दौरान रेल मंत्री ने पश्चिम बंगाल के रेल ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में 538 फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण किया जाएगा, जिससे रेल मार्गों पर यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा। इसके साथ ही 40 से अधिक अंडरपास परियोजनाओं के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त हो चुके हैं, जिससे काम में तेजी लाई जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने यह भी घोषणा की कि देशभर में अमृत भारत योजना के तहत 102 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिनमें पश्चिम बंगाल के भी कई स्टेशन शामिल होंगे। इसके अलावा गोपीबल्लभपुर-नयाग्राम रेल नेटवर्क के विस्तार पर भी काम किया जाएगा, जिससे आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में रेल क्षेत्र में कुल एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा, जिससे राज्य में आधारभूत संरचना को नई मजबूती मिलेगी। इसी के साथ कोलकाता मेट्रो के विकास को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके तहत आने वाले पांच वर्षों में लगभग 60 नई पीढ़ी की मेट्रो ट्रेनों को शामिल किया जाएगा।

शिक्षा में केवल परीक्षाओं को सुधारना काफी नहीं, पूरे 'सिस्टम' को बदलना होगा : सोनम वांगचुक

एजेंसी, नई दिल्ली

लद्दाख से दिल्ली आए सामाजिक एवं पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शुक्रवार को दिल्ली के जंतर-मंतर में कॉकरेच जनता पार्टी के नाम से चले सोशल मीडिया अभियान के आह्वान पर आयोजित प्रदर्शन में भाग लिया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए वांगचुक ने कहा कि केवल परीक्षा प्रक्रिया में सुधार काफी नहीं है, हमें बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलना होगा। अपने संबोधन में वांगचुक ने सरकार और व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग उठाई। उन्होंने एक बड़ा प्रस्ताव रखा और मांग की कि शिक्षा नीति बनाने वाले से लेकर सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि और सरकारी वेतन पाने वाले अधिकारी अपने बच्चों को भी अनिवार्य रूप से सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाएं। उन्होंने इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सराहना की और इसे विरोध के बजाय सरकार से किया गया एक 'आग्रह' बताया। हालिया परीक्षा विवादों पर बोलते हुए सोनम ने कहा कि शिक्षा का सवाल युवाओं की ज़िंदगी से सीधे जुड़ा है। जिस परीक्षा पर देश का युवा भरोसा करता है, अगर उसी में बेइमानियां होने लगें तो उम्मीदें टूट जाती हैं। युवाओं का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि यह युवाओं की बिल्कुल जायज मांग है। वे परीक्षाओं में केवल ईमानदारी मांग रहे हैं, कोई चांद-सितारे नहीं मांग रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे शीर्ष नेता इस पर खरे उतरेंगे और आने वाले दिनों में कोई अच्छा समाचार मिलेगा। उन्होंने निजी स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरों में तो शिक्षा की गुणवत्ता मिल जाती है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब गांवों के सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधरेगी।

तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और सचिव ने दिया इस्तीफ़ा

एजेंसी, चेन्नई

तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को शनिवार को उस समय झटका लगा, जब पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष करु नागराजन और प्रदेश सचिव सुमति वेंकटेश ने अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। दोनों नेताओं के इस्तीफे ऐसे समय सामने आए हैं, जब हाल ही में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने के बाद राज्य इकाई में राजनीतिक हलचल तेज बनी हुई है। प्रदेश सचिव सुमति वेंकटेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने इस्तीफे की जानकारी साझा करते हुए कहा कि उन्होंने भारी मन से तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश सचिव पद से इस्तीफा देने और पार्टी से अपने संबंध समाप्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि यह फैसला उन्होंने काफी सोच-विचार के बाद लिया है और उन्हें अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने प्रदेश सचिव के रूप में कार्यकाल के दौरान सहयोग, मार्गदर्शन और समर्थन देने वाले पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व, पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

साथ ही पार्टी नेतृत्व से उनका इस्तीफा स्वीकार कर उन्हें सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करने का अनुरोध किया। सुमति वेंकटेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व तथा भाजपा के राष्ट्रवाद, देशभक्ति और राष्ट्रसेवा के मूल्यों से उन्हें हमेशा प्रेरणा मिलती रही है। उन्होंने कहा कि यही सिद्धांत उनके राजनीतिक जीवन का आधार रहे हैं और भविष्य में भी उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे।

विश्व की अग्रणी कंज्यूमर हेल्थकेयर कंपनी हेलियन मप्र में स्थापित करेगी देश की पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई

एजेंसी, भोपाल

♦ लगभग 2000 करोड़ रुपये के निवेश पीथमपुर में बनने वाली इस इकाई का मुख्यमंत्री 8 जून को करेंगे भूमि-पूजन

विश्व की अग्रणी कंज्यूमर हेल्थकेयर कंपनी हेलियन मध्य प्रदेश के पीथमपुर स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई स्थापित करने जा रही है। करीब 2000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस इकाई का मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार, 08 जून को भूमि-पूजन करेंगे। जनसम्पर्क अधिकारी बबीता मिश्रा ने शनिवार को बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश का पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। यह परियोजना मुख्यमंत्री के यूनाइटेड किंगडम प्रवास और वहां आयोजित निवेश संवादों से सार्थक हुई है। निवेशकों के साथ हुई विस्तृत चर्चाओं और मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं के प्रभावी प्रस्तुतीकरण के बाद हेलियन ने प्रदेश में अपना निवेश विस्तार करने का निर्णय लिया। अब यह निवेश प्रस्ताव क्रियान्वयन के चरण में पहुंच चुका है। बताया कि लगभग दो हजार करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाली यह परियोजना प्रदेश में साकार हो रही महत्वपूर्ण विदेशी निवेश परियोजनाओं में शामिल है। पीथमपुर के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित की जाने वाली यह अत्याधुनिक इकाई मुख्य रूप से ओरल हेल्थ उत्पादों के निर्माण पर केंद्रित होगी। यहां उत्पादित सामग्री घरेलू बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ एशिया-प्रशांत, मध्य-पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र के अनेक देशों में निर्यात भी की जाएगी।

जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार, हेलियन वैश्विक स्तर पर कंज्यूमर हेल्थकेयर क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में शामिल है। सेंसोडाइन, क्रोसिन, ईनो, ओट्रिविन, आयोडेक्स, सेंट्रम तथा ऑस्टोकैल्शियम जैसे लोकप्रिय उत्पादों के माध्यम से कंपनी विश्वभर में अपनी मजबूत पहचान रखती है। लगभग 170 से अधिक देशों में उपस्थिति रखने वाली यह कंपनी स्वास्थ्य एवं स्व-देखभाल के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व स्थापित कर चुकी है। उन्होंने बताया कि परियोजना से लगभग 500 प्रत्यक्ष और 500 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही स्थानीय एमएसएमई इकाइयों, सप्लायर नेटवर्क, परिवहन, लॉजिस्टिक्स तथा अन्य सहायक उद्योगों को भी नए अवसर प्राप्त होंगे।

अमेरिकन व्हाइट-कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट 2026- एच-1बी वीजा से ग्रीन कार्ड का रास्ता बंद करने की कवायद, भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए नई चुनौती?

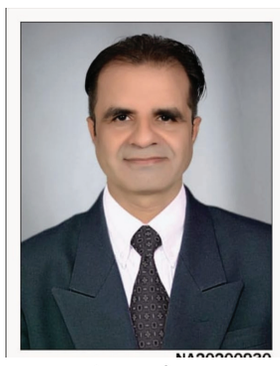

लोकतंत्र की शान

» अमेरिकन व्हाइट-कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट 2026 और भारत की वैश्विक रणनीतिः क्या भारत पहले से कर रहा है संभावित झटके की तैयारी?

» भारतीय मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सेमीकंडक्टर मिशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण तथा वैश्विक सप्लाई चेन से भारतीय प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक प्रतिभा, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और आर्थिक राष्ट्रवाद के बीच अमेरिका की आव्रजन नीति एक नए निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति ट्रम्प के सत्ता में लौटने के बाद अमेरिकीप्रशासन ने कानूनी आव्रजन कार्यक्रमों, विशेषकर एच-1बी वीजा प्रणाली, पर लगातार सख्ती का रुख अपनाया है। उच्च वेतन आधारित चयन प्रणाली की वकालत, वीजाआवेदनों की कड़ी जांच, रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में बाधाएं, विदेशी श्रमिकों की भर्ती पर बढ़ती निगरानी, अमेरिकी कर्मचारियों को प्राथमिकता देने वाली नीतियां तथा विदेशी छात्रों के लिए उपलब्ध अवसरों को सीमित करने जैसे अनेक कदम इस व्यापक नीति परिवर्तन का हिस्सा माने जा रहे हैं। इसी क्रम में टेक्सास से रिपब्लिकन सांसद द्वारा अमेरिकी संसद में प्रस्तुत अमेरिकन व्हाइट-कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट 2026 ने वैश्विक स्तर पर बहस छेड़ दी है। यदि यह विधेयक कानून का रूप लेता है तो एच-1बी वीजा धारकों के लिए ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का मार्ग अत्यंत कठिन हो जाएगा, वीजा अवधि घट सकती है, ओपीटी कार्यक्रम समाप्त हो सकता है और अमेरिका में कार्यरत लगभग 12 लाख भारतीय मूल के पेशेवरों तथा उनके परिवारों के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह केवल एक आव्रजन सुधार प्रस्ताव नहीं, बल्कि अमेरिका की बदलती आर्थिक, राजनीतिक और श्रम नीति का प्रतीक माना जा रहा है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि एच-1बी वीजा पिछले कई दशकों से अमेरिका की तकनीकी और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अमेरिकी कंपनियां विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में उच्च कौशल वाले विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करती हैं। विशेष रूप से भारतीय आईटी पेशेवरों ने इस कार्यक्रम का सबसे अधिक लाभ उठाया है।विश्व की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों में कार्यरत हजारों भारतीय इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा वैज्ञानिक और अनुसंधान विशेषज्ञ एच-1बी वीजा के माध्यम से अमेरिका पहुंचे हैं। यही कारण है कि एच-1बी वीजा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन भारत के तकनीकी समुदाय और छात्रों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। साथियों वैश्विक भू-राजनीति, आर्थिक राष्ट्रवाद और प्रतिभा आधारित प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अमेरिका द्वारा प्रस्तावित अमेरिकन व्हाइट-कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट 2026 केवल एक आव्रजन सुधार विधेयक नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे वैश्विक प्रतिभा प्रवाह, तकनीकी सहयोग और अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजार के पुनर्गठन के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। विशेष रूप से भारत के संदर्भ में यह विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है,क्योंकि एच- 1बी वीजा प्रणाली के सबसे बड़े लाभार्थियों में भारतीय पेशेवर शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा अपनाई गई अमेरिका फर्स्ट नीति, कानूनी और अवैध दोनों प्रकार के आव्रजन पर सख्ती,एच-1बी वीजानियमों की समीक्षा तथा अमेरिकी नौकरियों को प्राथमिकता देने की रणनीति ने भारत को यह संकेत पहले ही दे दिया था कि भविष्य में अमेरिकी श्रम बाजार भारतीय पेशेवरों के लिए पहले जैसा खुला नहीं रह सकता। यही कारण है कि भारत समानांतर रूप से अपने आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक विकल्पों को मजबूत करने में जुटा हुआ दिखाई देता है। साथियों, रिपब्लिकन सांसद का तर्क है कि लगभग चार दशकों के इतिहास में एच-1बी कार्यक्रम का व्यापक दुरुपयोग हुआ है। उनके अनुसार अमेरिकी नियोक्ताओं ने कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त कर अमेरिकी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्र के कर्मचारियों के अवसरों को सीमित किया है। उनका दावा है कि कंपनियों ने कर्मचारियों की कथित कमी का हवाला देकर सस्ते विदेशी श्रमिकों को प्राथमिकता दी जबकि अनेक अमेरिकी नागरिक रोजगार और वेतन संबंधी चुनौतियों का सामना करते रहे। इसी सोच के आधार पर उन्होंने अमेरिकन व्हाइट- कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट प्रस्तुत किया है, जिसका घोषित उद्देश्य अमेरिकी व्हाइट-कॉलर कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है।इस विधेयक का सबसे विवादास्पद प्रावधान एच-1बी वीजा से ग्रीन कार्ड तक पहुंचने के रास्ते को समाप्त करने की दिशा में उठाया गया कदम है। वर्तमान व्यवस्था में एच-1बी धारक अमेरिका में कार्य करते हुए रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यही कारण है कि लाखों विदेशी पेशेवर अमेरिका में दीर्घकालिक करियर और पारिवारिक भविष्य की योजना बनाते हैं। प्रस्तावित कानून इस अवधारणा को बदलना चाहता है। इसके अनुसार एच-1बी वीजा केवल अस्थायी कार्य वीजा रहेगा और इसे स्थायी निवास प्राप्त करने के साधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इससे अमेरिका में बसने की आकांक्षा रखने वाले लाखों लोगों की योजनाओं पर सटीकता से गहरा प्रभाव पड़ सकता है। साथियों, विधेयक का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ड्यूल इंटेंट सिद्धांत को कमजोर करना है।वर्तमान प्रणाली में एच -1बी धारक अमेरिका में अस्थायी रूप से काम करते हुए भविष्य में स्थायी निवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन प्रस्तावित व्यवस्था में आवेदक को यह साबित करना होगा कि उसका स्थायी निवास अमेरिका के बाहर है और वह अंततः अपने देश लौटने का इरादा रखता है। यह परिवर्तन अमेरिकी आव्रजन दर्शन में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है, क्योंकि इससे एच-1बी वीजा का स्वरूप मूलतः अस्थायी रोजगार कार्यक्रम तकसीमित हो जाएगा।विधेयक में एच-1बी वीजा की अधिकतम अवधि छह वर्ष से घटाकर केवल दो वर्ष करने काप्रस्ताव भी शामिल है। वर्तमान में अधिकांश पेशेवर छह वर्षों तक अमेरिका में रहकर कार्य कर सकते हैं और ग्रीनकार्ड प्रक्रिया लंबित होने की स्थिति में अतिरिक्त विस्तार भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि नई व्यवस्था लागू होती है तो कंपनियों के लिए दीर्घकालिक प्रतिभा प्रबंधन कठिन हो सकता है। कर्मचारियों को भी अपने करियर और पारिवारिक निर्णयों को लेकर अधिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव ग्रीन कार्ड प्रक्रिया लंबित रहने की स्थिति में मिलने वाले वीजा विस्तार को समाप्त करना है। आज अनेक भारतीय पेशेवर वर्षों तक ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा सूची में रहते हैं और इस दौरान एच-1बी विस्तार के माध्यम से अमेरिका में कार्य करते रहते हैं। प्रस्तावित कानून इस सुविधा को समाप्त कर सकता है। परिणामस्वरूप हजारों लोग ग्रीन कार्डस्वीकृत होने से पहले ही अमेरिका छोड़ने के लिए बाध्य हो सकते हैं।इस विधेयक का एक और महत्वपूर्ण आयामवैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण अर्थात ओपीटी कार्यक्रम को समाप्त करने का प्रस्ताव है।ओपीटी अमेरिकी विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करने वाले विदेशी छात्रों को डिग्री पूर्ण करने के बाद सीमित अवधि तक अमेरिका में कार्य करने का अवसर देता है। भारतीय छात्र इस कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थियों में शामिल हैं। ओपीटी समाप्त होने की स्थिति में अमेरिकी शिक्षा प्राप्त करने वाले विदेशी छात्रों के लिए रोजगार के अवसर काफी सीमित हो सकते हैं। इससे अमेरिका की उच्च शिक्षा प्रणाली की वैश्विक आकर्षण क्षमता पर भी प्रभाव पड़ सकता है।संसद और उनके समर्थकों का कहना है कि वर्तमान लॉटरी आधारित एच-1बी प्रणाली योग्यता और आर्थिक मूल्य के बजाय भाग्य पर आधारित है। इसलिए विधेयक में लॉटरी समाप्त कर उच्च वेतन वाली नौकरियों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव रखा गया है। इस मॉडल के समर्थकों का मानना है कि इससे केवल अत्यधिक कुशल और उच्च मूल्य वाले पेशेवरों को अवसर मिलेगा। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि इससे छोटे और मध्यम आकार के नियोक्ताओं के लिए प्रतिभाशाली विदेशी कर्मचारियों की भर्ती कठिन हो सकती है।ट्रंप प्रशासन के दौरान एच-1बी नीति को लेकर पहले भी अनेक सख्त कदम देखे गए थे और अब पुनः ऐसी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अमेरिकी श्रम बाजार में घरेलू कर्मचारियों को प्राथमिकता देने,विदेशी श्रमिकों के वेतन मानकों को बढ़ाने, आवेदनों की जांच को कठोर बनाने तथा रोजगार-आधारित आव्रजन को सीमित करने जैसे विचार रिपब्लिकन राजनीति के एक प्रभावशाली वर्ग में लंबे समय से मौजूद रहे हैं। अमेरिकन व्हाइट-कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट इन्हीं विचारों का विधायी विस्तार माना जा रहा है।

साथियों, इस पूरे विवाद का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय समुदाय पर पड़ सकता है। भारत एच-1बी वीजा प्राप्त करने वाले देशों में लंबे समय से अग्रणी रहा है। अमेरिकी तकनीकी उद्योग में भारतीय इंजीनियरों और पेशेवरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बड़ी संख्या में भारतीय परिवारों ने अमेरिका में स्थायी भविष्य की योजना एच-1बी से ग्रीन कार्ड की पारंपरिक यात्रा के आधार पर बनाई है। यदि यह मार्ग सीमित या बंद हो जाता है तो लाखों लोगों की दीर्घकालिक योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।भारतीय छात्रों के लिए भी यह प्रस्ताव चिंता का विषय है। हर वर्ष हजारों छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं और ओपीटी तथा बाद में एच-1बी वीजा के माध्यम से अपने करियर की शुरुआत करते हैं। यदि ओपीटी समाप्त हो जाता है और एच-1बी प्राप्त करना अधिक कठिन हो जाता है, तो अमेरिका की तुलना में अन्य देशों जैसे कनाडा , ऑस्ट्रेलिया , यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी अधिक आकर्षक विकल्प बन सकते हैं।हालांकि यह समझना आवश्यक है कि यह अभी केवल एक प्रस्तावित विधेयक है। अमेरिकी विधायी प्रक्रिया में किसी भी बिल को कानून बनने के लिए प्रतिनिधि सभा, सीनेट और राष्ट्रपति की स्वीकृति सहित अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। इसलिए इसका अंतिम रूप वर्तमान प्रस्ताव से भिन्न भी हो सकता है। फिर भी इसने अमेरिकी आव्रजन नीति की दिशा को लेकर गंभीर बहस शुरू कर दी है। समर्थकों का मानना है कि यह कानून अमेरिकी श्रमिकों की रक्षा करेगा, वेतन स्तर बढ़ाएगा और घरेलू प्रतिभा को प्राथमिकता देगा। दूसरी ओर आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका की तकनीकी श्रेष्ठता का एक बड़ा कारण दुनिया भर से प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने की क्षमता रही है। यदि विदेशी पेशेवरों और छात्रों के लिए अवसर सीमित किए जाते हैं तो दीर्घकाल में अमेरिकी नवाचार क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि अमेरिकन व्हाइट -कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट 2026 केवल एच-1बी वीजा सुधार का प्रस्ताव नहीं है,बल्कि यह अमेरिका में रोजगार, आव्रजन, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और आर्थिक राष्ट्रवाद के बीच चल रही व्यापक बहस का प्रतिनिधित्व करता है। यदि यह विधेयक पारित होता है तो एच-1बी वीजा का स्वरूप मूल रूप से बदल सकता है और विशेष रूप से भारतीय पेशेवरों, छात्रों तथा उनके परिवारों के लिएअमेरिका में अवसरों की संरचना नई चुनौतियों से भर सकती है। आने वाले महीनों में अमेरिकी कांग्रेस में इस विधेयक पर होने वाली चर्चा न केवल अमेरिका बल्कि वैश्विक प्रतिभा प्रवाह और अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजार की दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

-संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9284141425

राहुल की भविष्यवाणी जल्द गिर जायेगी मोदी सरकार? के मायने

लेखक- सौरभ वार्ष्णेय

भारतीय राजनीति में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब किसी बड़े नेता द्वारा सरकार के भविष्य को लेकर कोई बड़ी भविष्यवाणी की जाती है, तो वह राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाती है। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व वर्तमान सांसद राहुल गांधी ने यह बयान दिया कि वर्तमान सरकार एक वर्ष के भीतर गिर सकती है। उनके इस कथन ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी का मोदी सरकार एक साल में गिर जाएगी वाला बयान मई 2026 में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार परिषद की बैठक में दिया गया था। बाद में उन्होंने इसी तरह की बात दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में आदिवासी नेताओं को संबोधित करते हुए भी दोहराई। रिपोर्टों के अनुसार राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था अंदर से कमजोर हो रही है और अगले एक वर्ष में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आर्थिक संकट और जनदबाव के कारण सरकार पर असर पड़ेगा। इस बयान के बाद भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी और आरोप लगाया कि विपक्ष सरकार को अस्थिर करने की राजनीति कर रहा है।

बयान का राजनीतिक संदर्भ - राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय आया है जब विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट, सामाजिक तनाव और विभिन्न राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता जैसे विषय लगातार विपक्ष के एजेंडे में बने हुए हैं। ऐसे माहौल में सरकार के गिरने की संभावना जताना विपक्षी रणनीति का हिस्सा भी माना जा सकता है। राजनीति में इस प्रकार के बयान अक्सर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और जनता के बीच यह संदेश देने के लिए दिए जाते हैं कि सत्ता पक्ष अजेय नहीं है। विपक्ष अपने समर्थकों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करता है कि राजनीतिक परिवर्तन संभव है।

क्या वास्तव में सरकार पर खतरा है? किसी भी सरकार के गिरने की संभावना का आकलन केवल राजनीतिक भाषणों के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए संसद में संख्या बल, सहयोगी दलों का समर्थन, जनमत और राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण आवश्यक होता है।यदि सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है और सहयोगी दल उसके साथ मजबूती से खड़े हैं, तो केवल विपक्षी दावों के आधार पर सरकार का गिरना आसान नहीं होता। भारतीय लोकतंत्र में सरकारें सदन के बहुमत से चलती हैं और उनका भविष्य भी उसी से तय होता है। हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। यदि किसी गठबंधन में आंतरिक मतभेद बढ़ जाएं, सहयोगी दल अलग हो जाएं या कोई बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो जाए, तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन ऐसी संभावनाओं को तत्काल वास्तविकता मान लेना उचित नहीं होगा।

विपक्ष की रणनीति-राहुल गांधी के बयान को विपक्ष की व्यापक राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देखा जा सकता है। विपक्ष लगातार यह संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है और उसके प्रति असंतोष बढ़ रहा है।ऐसे बयान विपक्षी एकता को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और आगामी चुनावों की तैयारी के लिए माहौल बनाने में सहायक होते हैं। यह विपक्ष की उस कोशिश का हिस्सा हो सकता है जिसमें वह खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है।

सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया-सत्ता पक्ष ऐसे बयानों को सामान्यतः राजनीतिक हताशा या विपक्ष की निराशा बताकर खारिज करता है। सरकार समर्थकों का तर्क होता है कि जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इसलिए विपक्ष के दावों को वे राजनीतिक बयानबाजी से अधिक महत्व नहीं देते।

मालवीय नगर अग्निकांडः मुआवजे से नहीं, जवाबदेही और सुधार से बचेगी ज़िंदगी

लेखक- डॉ. सत्यवान सौरभ

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में 3 जून 2026 को लगी भीषण आग ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस दर्दनाक हादसे में इक्कीस लोगों की मौत और अनेक लोगों के घायल होने की खबर ने न केवल राजधानी बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। आग की लपटों से बचने के लिए लोगों को ऊँची इमारत से कूदते हुए देखा गया। सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में प्रसारित हुए दृश्य किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए अत्यंत पीड़ादायक थे। यह केवल एक दुर्घटना नहीं थी; यह उस व्यवस्था की विफलता का भयावह प्रमाण थी जो नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। हर बड़ी दुर्घटना के बाद कुछ दिन तक शोक, संवेदना, जांच और मुआवजे की घोषणाएं होती हैं। फिर धीरे-धीरे मामला सार्वजनिक स्मृति से ओझल हो जाता है। लेकिन मालवीय नगर की यह त्रासदी केवल शोक व्यक्त करके भुला देने योग्य घटना नहीं है। यह उन गहरे संरचनात्मक दोषों की ओर संकेत करती है जो भारत के महानगरों में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के साथ और अधिक खतरनाक रूप धारण कर चुके हैं। यह हादसा हमें मजबूर करता है कि हम पूछें—क्या हमारी इमारतें वास्तव में सुरक्षित हैं? क्या अग्नि सुरक्षा नियम केवल कागजों तक सीमित हैं? और क्या प्रशासन की भूमिका केवल दुर्घटना के बाद राहत बांटने तक सीमित रह गई है?

किसी भी बहुमंजिला इमारत में आग लगने की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है—सुरक्षित निकास, अग्निशमन उपकरण और समय पर बचाव। यदि किसी भवन में मौजूद लोगों को अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों और बालकनियों से छलांग लगानी पड़े, तो इसका अर्थ है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी थी। आग केवल भवन को नहीं जलाती, वह सुरक्षा संबंधी दावों और प्रशासनिक तैयारियों की वास्तविकता भी उजागर कर देती है। मालवीय नगर की घटना में यही हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, होटल में कई विदेशी नागरिक भी ठहरे हुए थे। यह तथ्य इस त्रासदी को और गंभीर बना देता है। भारत की राजधानी दुनिया भर के पर्यटकों, व्यापारियों और निवेशकों का स्वागत करती है। ऐसे में यदि राजधानी में ही सुरक्षा मानकों की स्थिति इतनी कमजोर हो कि विदेशी नागरिक भी असुरक्षित महसूस करें, तो यह केवल स्थानीय प्रशासन की विफलता नहीं बल्कि देश की अंतरराष्ट्रीय छवि पर भी प्रश्नचिह्न है। आधुनिक महानगर की पहचान केवल ऊँची इमारतों और चमकदार होटलों से नहीं होती, बल्कि वहाँ उपलब्ध सुरक्षा और आपदा प्रबंधन प्रणाली से होती है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शोक व्यक्त किया तथा मृतकों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। ऐसी संवेदनाएं आवश्यक हैं और संकट की घड़ी में पीड़ित परिवारों को सहायता मिलनी भी चाहिए। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि मुआवजा किसी खोए हुए जीवन को वापस नहीं ला सकता। आर्थिक सहायता दुख की तीव्रता को कम नहीं कर सकती। किसी परिवार का सदस्य, किसी बच्चे का पिता, किसी माता-पिता की संतान या किसी व्यक्ति का जीवनसाथी एक रकम से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए वास्तविक प्रश्न मुआवजे का नहीं, बल्कि रोकथाम का है। दिल्ली पुलिस द्वारा होटल मालिक के विरुद्ध गैर-इरादतन हत्या से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया जाना यह संकेत देता है कि जांच एजेंसियां इस घटना को केवल दुर्घटना नहीं मान रही हैं। यदि सुरक्षा नियमों की अनदेखी हुई, अग्निशमन मानकों का पालन नहीं किया गया या भवन निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ, तो यह केवल प्रशासनिक त्रुटि नहीं बल्कि आपराधिक लापरवाही है। ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जवाबदेही के अभाव में नियम केवल औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। लेकिन दोष केवल भवन मालिक का नहीं हो सकता। हमें यह भी देखना होगा कि निरीक्षण करने वाले अधिकारी कहाँ थे? क्या अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र समय-समय पर नवीनीकृत किए गए थे? क्या किसी निरीक्षण में कमियां सामने आई थीं? यदि आई थीं तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यदि नहीं आई थीं तो क्या निरीक्षण सही तरीके से हुए थे? इन प्रश्नों के उत्तर केवल इस मामले के लिए नहीं, बल्कि पूरे शहरी प्रशासन की कार्यप्रणाली को समझने के लिए आवश्यक हैं।

भारत के अधिकांश महानगर आज अव्यवस्थित शहरीकरण की समस्या से जूझ रहे हैं। संकरी गलियां, अवैध निर्माण, क्षमता से अधिक भीड़, पार्किंग की अव्यवस्था और सुरक्षा मानकों की अनदेखी लगभग हर शहर में सामान्य दृश्य बन चुके हैं। जब तक सब कुछ सामान्य रहता है, तब तक इन कमियों पर ध्यान नहीं जाता। लेकिन जैसे ही कोई आपदा आती है, यही कमियां जानलेवा साबित होती हैं। मालवीय नगर की तंग गलियों में दमकल वाहनों के पहुंचने में आई कठिनाइयों ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि शहरी योजना और आपदा प्रबंधन के बीच समन्वय का गंभीर अभाव है।

दिल्ली अकेली नहीं है। मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और अन्य महानगर भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अनेक इमारतें ऐसी हैं जहां अग्निशमन यंत्र या तो मौजूद नहीं हैं या वर्षों से उनकी जांच नहीं हुई। आपातकालीन निकास मार्ग अक्सर बंद रहते हैं। कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए सुरक्षा मानकों से समझौता कर लेते हैं। दुखद यह है कि कई बार प्रशासन भी इन उल्लंघनों के प्रति उदासीन बना रहता है।नहींः अग्नि सुरक्षा केवल भवन निर्माण का तकनीकी विषय नहीं है; यह नागरिक जीवन की रक्षा का मूल आधार है। विकसित देशों में अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन गंभीर अपराध माना जाता है। वहां नियमित निरीक्षण, अनिवार्य मॉक ड्रिल और कठोर दंड व्यवस्था लागू होती है। भारत में भी नियम मौजूद हैं, लेकिन समस्या उनके प्रभावी क्रियान्वयन की है। जब तक नियमों के उल्लंघन पर त्वरित और कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कागजी प्रावधान वास्तविक सुरक्षा में नहीं बदल सकते। इस त्रासदी ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है—क्या आम नागरिक अग्नि सुरक्षा के प्रति पर्याप्त रूप से जागरूक हैं? अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि आग लगने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। घबराहट, अफवाह और गलत निर्णय अक्सर जान-माल के नुकसान को बढ़ा देते हैं। विद्यालयों, कॉलेजों, कार्यालयों, होटलों और आवासीय परिसरों में नियमित अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण तथा मॉक ड्रिल अनिवार्य किए जाने चाहिए। सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है; यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। आवश्यकता इस बात की है कि इस घटना को केवल एक समाचार बनाकर न छोड़ दिया जाए। सभी बहुमंजिला होटलों, गेस्ट हाउसों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का विशेष सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। जिन भवनों में नियमों का उल्लंघन पाया जाए, उन्हें तत्काल बंद किया जाए। अग्निशमन विभाग को आधुनिक तकनीक, पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षित मानवबल उपलब्ध कराया जाए। साथ ही स्थानीय निकायों और नगर नियोजन एजेंसियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी ताकि भविष्य में आपातकालीन वाहनों को रास्ता मिल सके।

मिलावट-मुक्त भारत से ही विकसित भारत संभव

लेखक - ललित गर्ग

हर वर्ष 7 जून को मनाया जाने वाला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस केवल सुरक्षित भोजन की आवश्यकता का स्मरण कराने वाला दिवस नहीं है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, आर्थिक समृद्धि और सतत विकास के लिए एक वैश्विक संकल्प का अवसर भी है। वर्ष 2026 की थीम ''खाद्य सुरक्षाः विज्ञान की सक्रिय भूमिका'' इस बात पर बल देती है कि विज्ञान, अनुसंधान, तकनीक और प्रभावी निगरानी प्रणालियों के माध्यम से ही सुरक्षित खाद्य व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। लेकिन विडम्बना यह है कि भारत जैसे विशाल कृषि प्रधान देश में खाद्य पदार्थों, दवाइयों और दैनिक उपभोग की वस्तुओं में बढ़ती मिलावट इस लक्ष्य को गंभीर चुनौती दे रही है। मिलावट केवल खाद्य सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, यह राष्ट्र के स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, नैतिकता और वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ विषय है। जिस देश को विश्वगुरु और विकसित भारत बनने का सपना है, वहां यदि दूध, घी, मावा, मसाले, अनाज, मिठाइयां, फल-सब्जियां और यहां तक कि जीवनरक्षक दवाइयां भी मिलावट की शिकार हों, तो यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मानवता के विरुद्ध अपराध है। भारत में मिलावट का कारोबार आज एक संगठित आर्थिक अपराध का रूप ले चुका है। दूध में डिटर्जेंट, यूरिया और सिंथेटिक रसायनों का प्रयोग, मावे में स्टार्च और रासायनिक पदार्थों की मिलावट, मसालों में रंग और धूल, शहद में चीनी सिरप, खाद्य तेलों में सस्ते तेलों का मिश्रण तथा फलों और सब्जियों को कृत्रिम रसायनों से पकाना आम बात हो गई है। बाजार में बिकने वाले अनेक उत्पाद देखने में आकर्षक होते हैं, लेकिन भीतर से विषैले सिद्ध होते हैं। स्थिति तब और भयावह हो जाती है जब दवाइयों में मिलावट या नकली दवाओं का मामला सामने आता है। पिछले वर्षों में विभिन्न राज्यों में नकली अथवा घटिया दवाओं के सेवन से अनेक लोगों की मृत्यु और गंभीर स्वास्थ्य संकट की घटनाएं सामने आईं। राजस्थान के कोटा सहित कई स्थानों पर ऐसी खबरों ने पूरे देश को झकझोर दिया। जब जीवन बचाने वाली दवा ही मौत का कारण बनने लगे, तब यह केवल स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। मिलावट का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। कैंसर, किडनी रोग, हृदय रोग, यकृत संबंधी विकार, हार्मोन असंतुलन, बच्चों में कुपोषण, महिलाओं में स्वास्थ्य समस्याएं तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी जैसी अनेक गंभीर समस्याओं का संबंध दूषित एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों से जुड़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार असुरक्षित भोजन के कारण हर वर्ष करोड़ों लोग बीमार पड़ते हैं। भारत में भी स्वास्थ्य पर पड़ने वाला यह बोझ लगातार बढ़ रहा है। किन्तु मिलावट का संकट केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यह देश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रहार करता है। जब किसी देश के खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता संदिग्ध हो जाती है, तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है। निर्यात घटता है, विदेशी निवेश प्रभावित होता है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश पिछड़ जाता है। भारत कृषि उत्पादों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का एक बड़ा केंद्र बन सकता है, लेकिन मिलावट की समस्या उसकी संभावनाओं पर ग्रहण लगा रही है। इससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि मिलावट सामाजिक मूल्यों के क्षरण का प्रतीक बनती जा रही है। कुछ लोग त्वरित लाभ और अधिक मुनाफे की लालसा में दूसरों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। यह केवल आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि नैतिक पतन का भी संकेत है। जब समाज में ईमानदारी और उत्तरदायित्व की भावना कमजोर पड़ती है, तब ऐसे अपराध फलने-फूलने लगते हैं। सरकारों ने समय-समय पर खाद्य सुरक्षा और मानक कानून बनाए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) सहित अनेक संस्थाएं निगरानी और परीक्षण का कार्य करती हैं। फिर भी जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, निरीक्षण तंत्र की कमजोरी और कानूनी प्रक्रियाओं की धीमी गति मिलावट के विरुद्ध अभियान को प्रभावी नहीं बनने देती। अनेक मामलों में दोषियों को दंड मिलने में वर्षों लग जाते हैं, जिससे अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं।

संक्षिप्त समाचार

प्रज्ञानंद ने रच दिया इतिहास

नॉर्वे चेस टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय बने, विंसेंट कीमर को हराया

नई दिल्ली। ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने इतिहास रचते हुए नॉर्वे चेस का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। 20 साल के इस चेस स्टार ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर अपने अभियान का यादगार अंत किया। प्रज्ञानंद शुरुआत में 15 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर थे सही समय पर आगे आए और अपना क्लासिकल गेम जीतकर तीन अहम अंक हासिल किए। इससे उनके कुल अंक 18 हो गए और उन्हें एलीट चेस के सबसे प्रतिष्ठित खिताबों में से एक जीतने में मदद मिली।

प्रज्ञानंद ने रचा इतिहास

इस जीत के साथ चेन्नई में जन्मे इस स्टार खिलाड़ी ने वह उपलब्धि हासिल की जो 2013 में टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से भारतीय दिग्गज विश्वनाथन आनंद और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी. गुकेश भी हासिल नहीं कर पाए थे। नॉर्वे चेस में दूसरी बार हिस्सा लेने वाले प्रज्ञानंद की शुरुआत छह खिलाड़ियों वाले इस बड़े टूर्नामेंट में धीमी रही, लेकिन इवेंट के दूसरे हाफ में उन्होंने अपनी लय पकड़ ली। उनके इस सफर की सबसे बड़ी उपलब्धि नॉर्वे चेस के सात बार के चैंपियन और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल चेस में दो बार हराना रहा। इस इवेंट में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन गुकेश जब आखिरी दौर में मुकाबले से बाहर हो गए तो प्रज्ञानंद ने भारत की उम्मीदों को बनाए रखा और आखिरकार खिताब अपने नाम किया। यह तब संभव हुआ जब अमेरिकी ग्रैंडमास्टर वेस्ली सो, जो आखिरी राउंड से पहले 15.5 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे थे, अलीरेजा फिरोजा के खिलाफ अपना क्लासिकल गेम ड्रॉ पर खत्म करने को मजबूर हुए, जिससे उनका मुकाबला आर्मागेडन टाई-ब्रेक तक पहुंच गया। इस रिजल्ट ने प्रज्ञानंद के लिए रास्ता खोल दिया क्योंकि उन्हें पता था कि कीमर के खिलाफ क्लासिकल जीत उन्हें स्टैंडिंग में सबसे ऊपर पहुंचा देगी और एक यादगार खिताब दिला देगी।

फ्रेंच ओपन 2026

माजा च्वालिंस्का ने रचा इतिहास, फाइनल में पहुंचने वाली बनीं पहली क्वालिफायर खिलाड़ी

पेरिस। पोलैंड की 24 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी माजा च्वालिंस्का ने फ्रेंच ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। उन्होंने महिला एकल सेमीफाइनल में रूस की डायना श्नाइडर को सीधे सेटों में 7-6(4), 6-4 से हराकर पहली बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही वह रोलैंड गैरोस (फ्रेंच ओपन) के इतिहास में महिला एकल फाइनल तक पहुंचने वाली पहली क्वालिफायर खिलाड़ी बन गई हैं। विश्व रैंकिंग में 114वें स्थान पर मौजूद च्वालिंस्का ने इस टूर्नामेंट में अब तक कुल नौ मुकाबले जीते हैं। इनमें तीन मैच क्वालिफाइंग दौर और छह मैच मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम फाइनल तक पहुंचने वाली सिर्फ दूसरी क्वालिफायर बना दिया है। इससे पहले, यह कारनामा ब्रिटेन की एम्मा राडुकानू ने 2021 यूएस ओपन में किया था।

जहां उन्होंने खिताब भी जीता था। सेमीफाइनल मुकाबले में च्वालिंस्का ने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने स्पिन, गति और शॉट्स की दिशा में लगातार बदलाव करते हुए श्नाइडर पर दबाव बनाए रखा। इसके साथ ही उनकी बेहतरीन फिटनेस, तेज मूवमेंट और मजबूत डिफेंस ने जीत में अहम भूमिका निभाई। च्वालिंस्का और श्नाइडर के बीच हुआ सेमीफाइनल मुकाबला दो घंटे 10 मिनट तक चला। जीत के बाद भावुक नजर आईं च्वालिंस्का कोर्ट पर ही बैठ गईं। उन्होंने कहा, 'यह किसी सपने के सच होने जैसा है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने क्या हासिल किया है। मैं बहुत खुश हूं और शब्दों में अपनी भावना व्यक्त नहीं कर सकती।' इस उपलब्धि के साथ च्वालिंस्का एक और खास सूची में शामिल हो गई हैं। वह इवोन गूलागोंग (1971) और क्रिस एवर्ट (1973) के बाद रोलैंड गैरोस के मुख्य ड्रॉ में अपने पहले ही अभियान में फाइनल तक पहुंचने वाली केवल तीसरी महिला खिलाड़ी बनी हैं।

आयरलैंड-इंग्लैंड टी20 सीरीज और एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम का ऐलान

श्रेयस अय्यर कप्तान वैभव को अवसर

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। श्रेयस अय्यर को भारत की टी20 टीम का नया कप्तान बनाया गया है। वहीं, तिलक वर्मा को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आईपीएल 2026 में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दोनों सीरीज और एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में जगह दी गई है। हर्षित राणा और रवि बिश्नोई की टीम में वापसी हुई है। प्रिंस यादव को भी इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह दी गई है। हालांकि, उन्हें एशियन गेम्स के लिए टीम में जगह नहीं दी गई है। भारत को अपनी कप्तानी में टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जिताने वाले सूर्यकुमार यादव को किसी भी टीम में जगह नहीं दी गई है।

आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम में रखा गया है। वहीं, ईशान किशन और शिवम दुबे को भी टीम में जगह दी गई है। अय्यर कप्तानी की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे, तो तिलक को उपकप्तान बनाया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी और अक्षर पटेल को भी टीम में शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती भी टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं। तेज गेंदबाजी की कमान मोहम्मद सिराज के हाथों में सौंपी गई है, जबकि उनका साथ अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रिंस यादव देते हुए नजर आएंगे।

आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए भारतीय टी20 टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, वैभव सूर्यवंशी, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव।

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और वैभव सूर्यवंशी।

जुरेल श्रीलंका ए के खिलाफ 2 चार दिवसीय टेस्ट मैचों के लिए इंडिया ए के कप्तान होंगे

आकिब नबी को भी मिली टीम में जगह

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की अजीत अगरकर वाली चयन समिति ने श्रीलंका ए टीम के खिलाफ होने वाली 2 चार दिवसीय मैचों के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान कर दिया है। 25 जून से 5 जुलाई के बीच गाले में होने वाले 2 मैचों के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज इंडिया ए टीम की कप्तानी करेंगे। रणजी ट्रॉफी 2025-26 में शानदार गेंदबाजी करने वाले जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को भी टीम में जगह मिली है। देवदत्त पडिक्कल को उपकप्तान बनाया गया है।

जुरेल और पडिक्कल के अलावा, बल्लेबाजी लाइन-अप में साई सुदर्शन, ऋतुराज गायकवाड़ और एन जगदीसन शामिल हैं। विदर्भ के बल्लेबाज अमन मोखाड़े और आंध्र के बल्लेबाज शेख रशीद को भी पहली बार इंडिया ए टीम में जगह मिली है। इस दौरे पर भारतीय बल्लेबाजों का मुख्य लक्ष्य स्पिन के अनुकूल परिस्थितियों में ढलना और लाल कूकाबुरा गेंद के साथ खेलने की आदत डालना होगा।

गेंदबाजी आक्रमण में नबी, यश ठाकुर, अंशुल कंबोज और गुरनूर बरार को शामिल किया गया है। गुरनूर को हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ चल रहे एकमात्र टेस्ट मैच के लिए टेस्ट टीम में भी बुलाया गया था। आकिब का चयन अहम है, क्योंकि उन्होंने इस साल की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी और 60 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे।

लेग-स्पिनर जीशान अंसारी और ऑफ-स्पिनर सारांश जैन के साथ ऑलराउंडर आयुष बडोनी स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। आकिब और जीशान न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच की तैयारी के लिए भारतीय टीम के नेट गेंदबाज थे। गायकवाड़, बडोनी, ठाकुर और कंबोज पहले से ही श्रीलंका में हैं। वे इंडिया ए टीम के साथ 9 जून से दांबुला में श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के लिए गए हैं।

जुरेल श्रीलंका ए के खिलाफ 2 चार दिवसीय टेस्ट मैचों के लिए इंडिया ए के कप्तान होंगे

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की अजीत अगरकर वाली चयन समिति ने श्रीलंका ए टीम के खिलाफ होने वाली 2 चार दिवसीय मैचों के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान कर दिया है। 25 जून से 5 जुलाई के बीच गाले में होने वाले 2 मैचों के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज इंडिया ए टीम की कप्तानी करेंगे। रणजी ट्रॉफी 2025-26 में शानदार गेंदबाजी करने वाले जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को भी टीम में जगह मिली है। देवदत्त पडिक्कल को उपकप्तान बनाया गया है।

जुरेल और पडिक्कल के अलावा, बल्लेबाजी लाइन-अप में साई सुदर्शन, ऋतुराज गायकवाड़ और एन जगदीसन शामिल हैं। विदर्भ के बल्लेबाज अमन मोखाड़े और आंध्र के बल्लेबाज शेख रशीद को भी पहली बार इंडिया ए टीम में जगह मिली है। इस दौरे पर भारतीय बल्लेबाजों का मुख्य लक्ष्य स्पिन के अनुकूल परिस्थितियों में ढलना और लाल कूकाबुरा गेंद के साथ खेलने की आदत डालना होगा।

गेंदबाजी आक्रमण में नबी, यश ठाकुर, अंशुल कंबोज और गुरनूर बरार को शामिल किया गया है। गुरनूर को हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ चल रहे एकमात्र टेस्ट मैच के लिए टेस्ट टीम में भी बुलाया गया था। आकिब का चयन अहम है, क्योंकि उन्होंने इस साल की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी और 60 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे।

लेग-स्पिनर जीशान अंसारी और ऑफ-स्पिनर सारांश जैन के साथ ऑलराउंडर आयुष बडोनी स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। आकिब और जीशान न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच की तैयारी के लिए भारतीय टीम के नेट गेंदबाज थे।

व्यापार

अडानी की कंपनी के बेचे गए 5750 करोड़ के शेयर

नईदिल्ली, एजेंसी। अमेरिका की दिग्गज निवेश कंपनी तत्त्व पार्टनर्स ने लगभग 5,750 करोड़ रुपये के ब्लॉक डील के जरिए अडानी ग्रुप की दो कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम की है। यह पूरी हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड ने खरीद ली है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी ह्स्श्र के ब्लॉक डील डेटा के अनुसार पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड ने अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर बेचे। इस डील के तहत अडानी एंटरप्राइजेज के 1.64 करोड़ शेयर 2,913.4 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचे गए। इस तरह, डील की कुल वैल्यू लगभग 4,789 करोड़ रुपये रही। वहीं, तत्त्व ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के 63.66 लाख शेयर 1,504.8 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचे, जिनकी कुल वैल्यू लगभग 958 करोड़ रुपये थी। इन दोनों डील की कुल वैल्यू लगभग 5,747 करोड़ रुपये थी।

यह हिस्सेदारी बिक्री अडानी ग्रुप के शेयरों में पिछले एक साल में आई जबरदस्त तेजी के बाद हुई है। बता दें कि वर्ष 2023 में अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई थी लेकिन उसके बाद कई कंपनियों ने मजबूत वापसी की है। उन शुरुआती बड़े संस्थागत निवेशकों में शामिल था जिसने हिंडनबर्ग विवाद के बाद अडानी समूह पर भरोसा जताया था।

कंपनी के बारे में

अडानी एंटरप्राइजेज की बात करें तो इस ग्रुप की मुख्य कंपनी है। यह एयरपोर्ट, सड़क, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर और माइनिंग सर्विस जैसे कई तरह के बिजनेस चलाती है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट-सेक्टर ट्रांसमिशन कंपनियों में से एक है और स्मार्ट मीटरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है।

नवजात शिशुओं के खून में मिल रहे हैं प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल्स

बायोप्लास्टिक अपनाने का समय आ गया!

नई दिल्ली, एजेंसी। यह सुनने में बेहद डरावना लगता है, लेकिन यह सच्चाई है। जी हां, प्लास्टिक का उपयोग करते करते हम इतने तल्लीन हो गए हैं कि कैसे इसके माइक्रो पार्टिकल्स हमारे शरीर में घुस गए, पता ही नहीं चला। स्थिति तो यह है कि नवजात शिशुओं के खून में भी प्लास्टिक के बहुत ही छोटे या माइक्रो पार्टिकल्स मिल रहे हैं। इसलिए समय आ गया है कि बायो-प्लास्टिक अपनाया जाए। यह कहना है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। अवसर था बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड और लखनऊ छावनी बोर्ड के साथ बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 के लॉन्चिंग का।

उद्योग जगत ने बढ़ाया हाथ

जीवन के हर क्षेत्र में प्लास्टिक की बढ़ती घुसपैठ को देखते हुए बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड ने पहल की है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बायोप्लास्टिक इको-सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

इस पहल के तहत लखनऊ छावनी बोर्ड के साथ बीसीएमएल का एमओयू हुआ। इसका उद्देश्य दैनिक जीवन में प्लास्टिक के बदले बायोप्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा देना।

माइक्रोप्लास्टिक से हर साल लाखों मौत- वह कहते हैं 'मैं कोई डरावनी कहानी यहां पर नहीं बता रहा हूं, बल्कि यह वैज्ञानिक तथ्य है जो अब हर दिन नए-नए सामने ला रहे हैं।

बलरामपुर चीनी मिल्स शेयर का भाव

शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट दिखी थी। बीएसई सेंसेक्स 116 अंक गिर कर बंद हुए थे। तब भी बलरामपुर चीनी मिल्स के शेयरों में तेजी दिखी।

प्लास्टिक से बायोप्लास्टिक कैसे अलग है

प्लास्टिक बनाने के लिए जो दाना बनता है, वह क्रूड ऑयल को क्रैक करके बनाया जाता है। इसका यदि जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग किया जाए तो यह ठीक है। लेकिन इसे यूं ही फेंक दिया जाए तो सैकड़ों क्या, हजारों साल में नहीं सड़ते-गलते। इसके उलट बायोप्लास्टिक के दाने का निर्माण गन्ने, मक्के और गेहूं जैसे जैविक फसलों के उत्पाद से होते हैं। वैज्ञानिक परीक्षण में साबित हुआ है इसे फेंकने पर कुछ ही महीने में यह गलना शुरू हो जाता है। साल भर में तो यह पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है। बीसीएमएल और लखनऊ छावनी बोर्ड के बीच गुरुवार को इस बारे में एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ था। उस अवसर पर राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे। इसी अवसर पर उन्होंने कहा 'जब भी एक नवजात बच्चे की जांच की कराई जाए तो उसमें भी प्लास्टिक के बहुत ही माइक्रो पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे-छोटे पार्टिकल्स मिल रहे हैं ...हम बोतल बंद पानी पीते हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593 RNI No.: DELHIN/2008/23928
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)